स्वदेशी पत्रिका

वर्ष–19, अंक–5, वैशाख–ज्येष्ठ 2068, मई 2011

संपादक
विक्रम उपाध्याय

कार्यालय
धर्मक्षेत्रा, सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग रामकृष्णपुरम, नयी दिल्ली–110022 से प्रकाशित
दूरभाष : 011–26184595
स्वदेशी जागरण समिति की ओर से ईश्वर दास महाजन द्वारा कॉम्पीटेंट बाइन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली–32 से मुद्रित।

आवरण कथा-4

मायावती हो या सोनिया गांधी मौखिक रूप से सबकी प्राथमिकता किसान हैं। फिर भी किसान बर्बाद हो रहे हैं। यह कम दुखद नहीं है कि 100 करोड किसानों के रहते हुए उनके पास सिर्फ 27 फीसदी भूमि का मालिकाना हक रह गया है। शेष सभी भूमि मोटे साहूकारों या निजी कंपनियों के हाथ चली गई हैं। क्या होगा इस देश का।

अनुक्रम

आवरण लेख : जोर जबर्दस्ती से अधिग्रहण
पहले जमीन गई अब जान भी जा रही है
– विक्रम उपाध्याय /4

आंदोलन
राष्ट्रीय परिषद् बैठक में पारित प्रस्ताव /7

कृषि
खेती पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों की निगाहें
– भारत डोगरा /10

पलायन
गांव से शहर की ओर पलायन के कारण एवं निवारण
– डॉ. नन्द सिंह नरूका /12

मुद्दा
बढ़ती आबादी, बढ़ता खाद्य संकट
– जयंतीलाल भंडारी /15

प्रतिक्रिया
शून्य सहनशीलता का सच
– बलवीर पुंज /17

सामयिकी : लड़ाई का अगला मोर्चा
– ब्रह्मा चेलानी /19

तर्क–वितर्क : आज भी नहीं मिल पाया है श्रमिकों को सम्मान
– बजरंग मुनि /22

सवाल : आम आदमी पर कर का बोझ
क्रिकेट और कारपोरेट को दी जाती है भारी कर रियायतें
– डॉ. कृष्णस्वरूप आनन्दी /26

संस्कृति : सामाजिक मूल्यों का पतन और स्वदेशी
– विश्वतोष श्रीवास्तव /28

लेख : भ्रष्टाचार हिंसा, सदाचार अहिंसा है
– राजेन्द्र सिंह /29

एक नज़र : भ्रष्टाचार के बाद देश
– डॉ. सूर्य प्रकाश अग्रवाल /32

दृष्टिकोण :
जैतापुर : आणविक ऊर्जा के विरोध में उठती आवाज
– डॉ. अश्विनी महाजन /35

पाठकनामा /2

पाठकनामा

जन एकता न बनने के कारण फैलता है रिश्वत

अक्सर मैं स्वदेशी पत्रिका पढ़ता हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि देश की सारी समस्याएं हमारे द्वारा ही पैदा की गई हैं। हमारा देश भ्रष्टाचार के दलदल में आकंठ डूबा हुआ है। कोई भी सरकारी काम रिश्वत दिए बगैर हो ही नहीं सकता। ईमानदार आदकी को सरकारी विभाग के इतने चक्कर लगाने पड़ते हैं कि वह भी हार मान लेता है। इस रिश्वत की संस्कृति पर हमला करने की जरूरत है। सरकारी कार्यालयों में रिश्वत देने के बजाय धरना व प्रदर्शन करना चाहिए ताकि रिश्वत लेने वाले कर्मचारी को अपनी नौकरी जाने का भय रहे। रिश्वत लेने वाले को तुरंत नौकरी से निकाल दिया जाए और उसकी पेंशन इत्यादि न दी जाए ।

— अमरेश कुमार, आया नगर, नई दिल्ली

अन्ना के बाद बाबा रामदेव

अन्ना हजारे के आमरण अनशन की हवा सरकार ने निकाल दी। लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ जैसे ही लामबंद हुए, सरकार और कांग्रेस के नुमाइंदों ने एक कमेटी बनाने की औपचारिक घोषणा कर अन्ना की अनशन तुड़वा दी। बाद में इन्हीं लोगों ने अन्ना के लोगों को बदनाम करने की साजिश रच कर आंदोलन को पटरी से उतार दिया। अब बाबा रामदेव अनशन करने जा रहे हैं। बिना लोक दबाव के सरकार झुकेगी नहीं और भ्रष्टाचार कम नहीं होगा। लेकिन इस बात की सावधानी बरतनी होगी कि कहीं अन्ना की तरह बाबा रामदेव को भी सरकार बदनाम करने की मुहिम न शुरू कर दे। इसके पहले दिग्विजय सिंह इस योगगुरु की संपत्ति को लेकर जनता में आशंका फैलाने की कोशिश कर चुके है। मेरी बाबा से प्रार्थना है कि इस बार बिना किसी निष्कर्ष के आंदोलन स्थगित न करे। भ्रष्टाचार का मुद्दा किसी एक व्यक्ति का मुद्दा नहीं है। इससे पूरा देश प्रभावित है। हर आदमी त्रस्त है। इससे भारत को मुक्ति मिलनी ही चाहिए।

— आयुषी उपाध्याय, गाजियाबाद

दो पंक्तियां

मेरी रगो में खून, देश के लिए है
सींच दो इससे नई पीढ़ी के सपने को
कर्म पथ पर बढ़ते रहे और जीए सिर उठांकर
करे काम न ऐसा कोई जग के उस पर हसने को

— राजीव, दिल्ली

आवश्यक नहीं कि इस अंक के भीतर प्रस्तुत लेखकों के विचार स्वदेशी पत्रिका के संपादक मंडल के विचारों से मेल खाते हों। पाठकों की जानकारी के लिए उन्हें यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

संपादकीय कार्यालय

'धर्मक्षेत्र' शिव शक्ति मन्दिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

दूरभाष : 011–26184595 • ई–मेल : swadeshipatrika@rediffmail.com

अगर आप घर बैठे स्वदेशी पत्रिका चाहते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट, मनीऑर्डर अथवा चेक द्वारा शुल्क *'स्वदेशी पत्रिका'* दिल्ली के नाम भेजने का कष्ट करें।

वार्षिक सदस्यता शुल्क : 100 रुपए
आजीवन सदस्यता शुल्क: 1,000 रुपए

यदि शुल्क भेजने के उपरांत भी आपको पत्रिका समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो तुरंत पत्रिका कार्यालय को सूचित करें।

(ध्यानार्थ : कृपया अपना नाम व पता साफ अक्षरों में लिखें)

उन्होंने कहा

ओसामा हजारों निर्दोषों की हत्या का दोषी था। उसके मारे जाने भर से ही अमेरिका का अभियान खत्म नहीं हुआ। हम एक बार फिर याद दिला दें कि अमेरिका जो ठान लें वह करके दिखाता है।

— बराक ओबामा

पाकिस्तान का यह बहाना अब नहीं चलेगा कि उसे लादेन के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। यह समय चुप रहने के बजाए बोलने का है। अब पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित कर देना चाहिए।

— सलमान रूशदी

मुंबई आतंकी हमला अमेरिका पर हुए 9/11 हमले से कम नहीं है। भारतीयों की जान अमेरिकियों से कम नहीं है। हमें भी उसी तरह अपने दुश्मनों पर कार्रवाई का अधिकार है।

— यशवंत सिन्हा

करे सरकार भरे जनता

महंगाई के मुद्दे पर सरकार के विफल होने के बाद रिजर्व बैंक के उपर ही यह जिम्मेदारी आती है कि वह अपने तरीके से महंगाई के आकड़े कम करे। पिछले हफ्ते घोषित मौद्रिक नीति में रिजर्व बैंक ने एक बार फिर कर्ज महंगा करने और मांग को नीचे लाने का फैसला किया। रेपो रेट में आधा फीसदी बढ़ोतरी का मतलब ही यह है कि बैंकों को अब रिजर्व बैंक से ऊंची दर पर पैसा मिलेगा और बैंक अब महंगी दर पर उपभोक्ताओं या व्यावसायियों को कर्ज देंगे। यानी अब उद्योग धंधों को मुश्किल हो जाएगी अपने लिए पैसे जुटाने में। साथ ही आम उपभोक्ता जो अपनी जरूरतों के लिए कर्ज लेता है, उसे भी मायूस बैठना पड़ेगा। वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने रिजर्व बैंक के इस कदम को जायज ठहराते हुए यह कहा है कि तेजी से बढ़ रही मुद्रा स्फीति की दर को कम करने के लिए यही उपाय था। यानी सरकार मान रही है कि उसके पास महंगाई कम करने का कोई रास्ता नहीं बचा है। सरकार की अपनी विफलता का खामियाजा आम आदमी या उद्योग भुगते। अब घर खरीदना महंगा, कार खरीदना महंगा और धधा चलाना भी मुश्किल। अब लोग यह मानने लगे हैं कि रिजर्व बैंक के इस कदम से कर्ज की दर दहाई अंक में पहुंच जाएगी। अब यह सरकार ही निश्चित करें कि इतनी महंगी अर्थव्यवस्था को लेकर किस तरह से 2020 तक आर्थिक सुपर पॉवर बनने का सपना देख रही है। आज भी अमरीका, जापान या अन्य विकसित देशों में कर्ज पर ब्याज दर पांच फीसदी से अधिक नहीं है। अर्थात् उधोग धंधे या व्यापार के लिए आज भी वे देश बड़े निवेशकों के लिए प्राथमिकता वाले देश होंगे। भारत ने इस मामले में अपनी बढ़त खो दी है। ज्यादा दूर क्यों जाए चीन का ही उदाहरण लें। आसानी से वित्त उपलब्ध होने और अनुकूल नियम कानून होने के कारण ही भारत की कंपनियां यहां से चीन जाने लगी है। तमाम बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने यहां से डेरा–डंडा उठाकर चीन में जमा लिया है। चीन यूं ही दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश नहीं बन गया है लेकिन हमारे यहां तो सरकार महंगाई के मुद्दे से ही नहीं लड़ पा रही है। लगातार पांच वर्षों से महंगाई बढ़ रही है और सरकार एक ही बात कहती है कि उसके पास जादू की छड़ी नहीं है। बहरहाल नई मौद्रिक नीति न सिर्फ कर्ज को महंगा करेगी बल्कि विकास को भी अवरूद्ध करेगी। आवासीय ऋण महंगे होने से सिर्फ रियल एस्टेट कारोबार ही नहीं बैठेगा बल्कि इस्पात, सीमेंट और इससे जुड़े अन्य उद्योग धंधे भी चौपट होंगे। सबसे बड़ी समस्या मजदूरों की आएगी, क्योंकि रियल एस्टेट क्षेत्र में इन दिनों सबसे अधिक रोजगार मिल रहा है। देश की औद्योगिक विकास दर पर भी असर पड़ेगा। इस समय ढांचागत क्षेत्र में कई परियोजनाएं चल रही हैं। यदि उन्हें समय पर वित्तीय साधन उपयुक्त दर पर नहीं मिला तो ये सारी योजनाएं ठप्प पड़ सकती है और कहने की आवश्यकता नहीं है कि इनकी लागत में हजारों करोड़ों रूपयों की वृद्धि हो सकती है। रिजर्व बैंक की यह दलील है कि कर्ज महंगे करने से चीजों की मांग कम हो जाएगी और मांग कम होने से कीमत अपने आप नीचे आ जाएगी। रिजर्व बैंक भी जानता है कि रेपो रेट में वृद्धि कोई दीर्घकालीन उपाय नहीं है। बल्कि यह बैंकिंग उद्योग के लिए प्रतिकूल ही है क्योंकि कर्ज पर ब्याज की दरें बढ़ाने के साथ–साथ जमा पर भी ब्याज दरें बढ़ाने पड़ेगी जो बैंक के लिए एक तरह से देनदारी है। बैंकिंग उद्योग के लिए कभी भी यह लाभदायक स्थिति नहीं होती। बैंक कम दर पर पैसा उठाकर उद्योग को वित्त पोषण करता है तो उसे लाभ होता है। इसके विपरीत वह अधिक ब्याज दर पर पैसा उठाकर और कर्ज कम जारी कर, नुकसान में होता है। हालांकि यह मौद्रिक नीति सिर्फ तीन महीने के लिए है आने वाले अगले तीन महीनों में अगर स्थिति सुधरती है। तो वापस कर्ज सस्ता हो सकता है लेकिन यह जिम्मेदारी सरकार पर होती है कि वह महंगाई पर काबू पाए और लोगों की आय बढ़ाने में सहायता करें और उद्योग धंधों के लिए उचित माहौल बनाए। फिलहाल यह रास्ता कठिन नजर आता है।

जोर जबर्दस्ती से अधिग्रहण

पहले जमीन गई अब जान भी जा रही है

दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में किसानों ने अपनी जमीन के अधिग्रहण की कीमत सिर्फ 200 रुपये प्रति वर्ग गज बढ़ाने के लिए आंदोलन किया। जब शासन ने नहीं सुनी तो आंदोलन किया। आंदोलन से बात नहीं बनी तो सरकारी कर्मचारियों को बंधक बनाया तब भी सरकार के कान पर जू नहीं रेंगा। नतीजा ग्रामीणों और पुलिस के बीच भिड़ंत हुई तीन पुलिस वाले मारे गए। जिलाधिकारी को गोली लगी। 15 किसान मरणासन्न स्थिति में अस्पताल में पड़े हैं।

■ विक्रम उपाध्याय

देश एक स्वरूप दो। और दोनों एक दूसरे के एक दम विपरीत कैसे तो ये खबर पढ़िए।

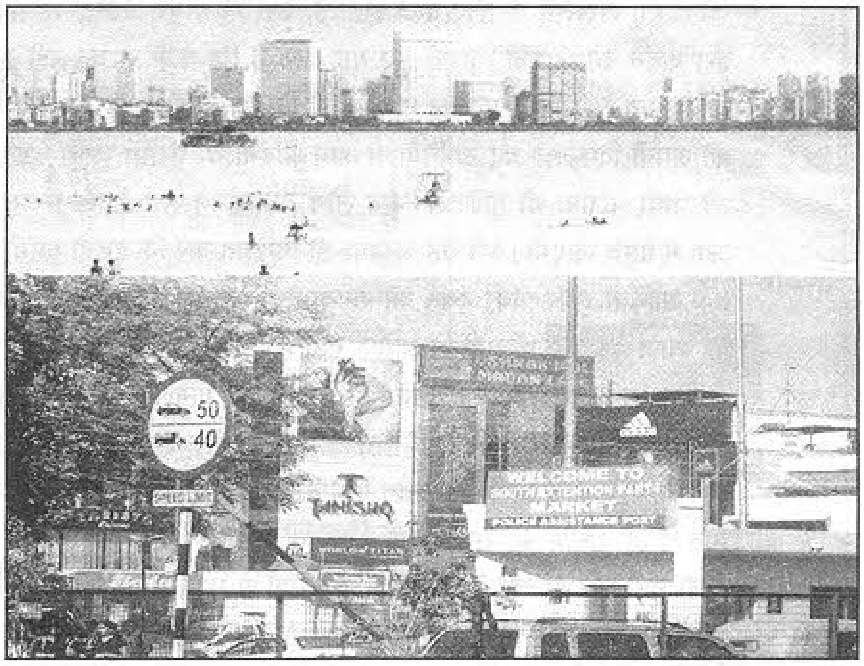

मुंबई में एक 3000 वर्ग फीट का फ्लैट 20 करोड़ में बिका है। तीन कमरों के इस फ्लैट की इतनी बड़ी कीमत इस लिए लगाई है, क्योंकि इससे समुद्र दिखता है. . .एक और खबर दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में एक 600 वर्ग गज का भूखंड 61.5 करोड़ में बिका है. . .. .यह उस भारत की तस्वीर है जहां विलासिता के लिए पैसे खर्च ने की कोई सीमा नहीं है।

मुंबई में एक 3000 वर्ग फीट का फ्लैट 20 करोड़ में बिका है। तीन कमरों के इस फ्लैट की इतनी बड़ी कीमत इस लिए लगाई है, क्योंकि इससे समुद्र दिखता है। इसमें सभी सुख सुविधाएं हैं और इसके मालिक के पास इतनी बड़ी रकम है कि वह 20 करोड़ सिर्फ एक फ्लैट खरीदने के लिए खर्च कर सकता है। एक और खबर दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में एक 600 वर्ग गज का भूखंड 61.5 करोड़ में बिका है। इस पर जो फ्लैट बनेंगे उनमें से किसी की भी कीमत 20 करोड़ रुपये से कम नहीं होगी।

क्या इतने पैसे में घर खरीदने वाले लोग हैं। बिल्डर का जवाब है अभी बनना शुरू नहीं हुआ और हमने द्वितीय तल ..50 करोड़ में बेच दिया है। यह उस भारत की तस्वीर है जहां विलासिता के लिए पैसे खर्च ने की कोई सीमा नहीं है। अब एक और भारत देखिए दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में किसानों ने अपनी जमीन के अधिग्रहण की कीमत सिर्फ 200 रुपये प्रति वर्ग गज बढ़ाने के लिए आंदोलन किया। जब शासन ने नहीं सुनी तो आंदोलन किया। आंदोलन से बात नहीं बनी तो सरकारी कर्मचारियों को बंधक बनाया तब भी सरकार के कान पर जू नहीं रेंगा। नतीजा ग्रामीणो और पुलिस के बीच भिड़ंत हुई तीन पुलिस वाले मारे गए। जिलाधिकारी को गोली लगी। 15 किसान मरणासन्न स्थिति में अस्पताल में पड़े हैं। सरकार और जनता के बीच सीधी लड़ाई छिड़ गई हैं। महिलाएं और बच्चे गांव छोड़कर भागने लगे हैं। दो सौ रुपये देने की स्थिति में सरकार नहीं है। दो सौ करोड़ रुपये संघर्ष में खर्च करना गवारा है।

ये इक्की दुक्की घटनाएं नहीं है। जब से साहुकारों और बड़ी कंपनियों के इशारे पर किसानों की जमीनें हड़पने की

दरअसल कॉरपोरेट और सरकार की मिली भगत के कारण किसानों को सीधे पलायन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अभी तक देश में इस बात पर कोई सहमति हीं नहीं बनी कि भूमि छीनने से पहले किसानों को पुनर्स्थापित कैसे किया जाए।

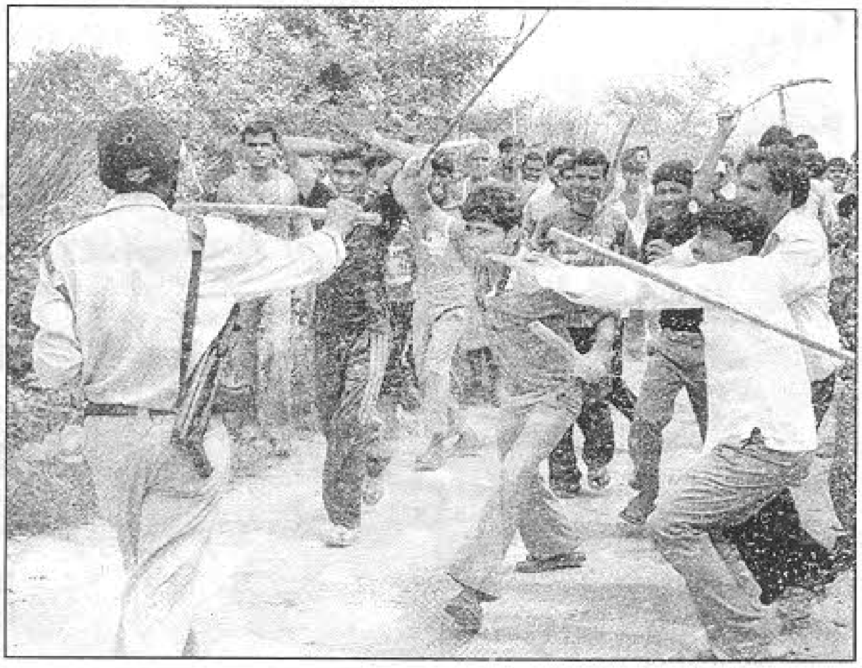

नीति बनी है तभी से ही देश भौगोलिक स्तर पर नहीं, मानसिक स्तर पर दो भागों में बंट गया है। एक के पास सब कुछ है और वह सबका अपने पास करने के लिए आतुर है। एक के पास बस कहने को थोड़ी बहुत जमीन बची है वह भी छिनी जा रही है।

स्थानीय पुलिस से लेकर मिलिटी तक उनके सामने खड़ी कर दी जा रही है। ऐसा सिर्फ नोएडा या ग्रेटर नोएडा में नहीं हो रहा है पूरे देश में हो रहा है। नोएडा से पहले अलीगढ़ में कुछ महीनों पहले ऐसे ही संघर्ष हुआ था एक पुलिस वाले समेत चार लोगों की जान गई थी। सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा। किसानों की सुनने के बजाय उत्तरप्रदेश की सरकार ताज एक्सप्रेस वे के निर्माण पर ज्यादा गंभीर है। उसके रास्ते में आने वाले हर आदमी के लिए गोली तैयार है। दो अरब डॉलर की लागत से यह छह लेन की हाईवे बन रही है। उस पर अमीर की गाड़ियों की रफ्तार दो सौ किलोमीटर की हो जाएगी। किसान अपनी जमीन से बाहर हो जाएंगे। किसानों की मांग है कि उनकी जमीन बाजार दर पर खरीदी जाए, सरकार कहती है कि वह अपनी दर पर खरीदेगी, दोनों दरों में 100 फीसदी की अंतर है। किसानों के अनुसार अभी जो मुआवजा मिल रहा है वह बाजार दर का आधा है।

भू–अधिग्रहण को लेकर अभी तक जो भी संघर्ष सामने आए हैं, उनसे लगभग शत प्रतिशत किसी न किसी कॉरपोरेट घराने के हित जुड़े हैं। कहीं जेपी का नाम है तो कहीं पास्को का। कहीं ट्रिडेंट है तो कहीं टाटा है। कभी वेदांता के हित सामने आते हैं तो कभी सालिम समूह के। किसी भी किसान ने समाज और सामाजिक हितों से जुड़ी परियोजनाओं के लिए विरोध

भू–अधिग्रहण को लेकर अभी तक जो भी संघर्ष सामने आए हैं, उनसे लगभग शत प्रतिशत किसी न किसी कॉरपोरेट घराने के हित जुड़े हैं। कहीं जेपी का नाम है तो कहीं पास्को का। कहीं ट्रिडेंट है तो कहीं टाटा है। कभी वेदांता के हित सामने आते हैं तो कभी सालिम समूह के। किसी भी किसान ने समाज और सामाजिक हितों से जुड़ी परियोजनाओं के लिए विरोध किया ही नहीं। सभी जगह की राज्य सरकारें इन कॉरपोरेट समूह के लिए कोई भी हद पार करने को तैयार है।

उड़ीसा की निलयगिरि पहाड़ियों में बॉक्साइट की खनन के लिए आई ब्रिटेन की कपंनी वेदांता ने वायदा तो किया ग्रमीणों को लाभ देने का, लेकिन किया क्या? मायावती हो या सोनिया गांधी मौखिक रूप से सबकी प्राथमिकता किसान हैं। फिर भी किसान बर्बाद हो रहे हैं। यह कम दुखद नहीं है कि 100 करोड किसानों के रहते हुए उनके पास सिर्फ 27 फीसदी भूमि का मालिकाना हक रह गया है। शेष सभी भूमि मोटे साहुकारों या निजी कंपनियों के हाथ चली गई हैं। क्या होगा इस देश का।

किया ही नहीं। सभी जगह की राज्य सरकारें इन कॉरपोरेट समूह के लिए कोई भी हद पार करने को तैयार है।

उड़ीसा सरकार लैंको पावर परियोजना और वेदांता के लिए कुछ भी करने को तैयार है। आदिवासियों को भू वचित करने के साथ साथ पर्यावरण से समझौता करने के लिए नवीन पटनायक की सरकार कुछ भी कर गुजर रही है।

पश्चिम बंगाल की कहानी किसे याद नहीं होगी। नंदी ग्राम से लेकर सिंगूर तक न जाने कितने किसानों के खून बहे।

मामला क्या था, यहीं न कि बुद्धदेव भट्टाचार्य की सरकार इस बात पर अड़ी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए नंदी ग्राम में इंडोनेशिया के सालीम समूह और सिंगूर में टाटा को कौड़ियों के भाव जमीन देंगे ही। कहने की आवश्यता नहीं कि बंगाल की सरकार की इस जिद ने दर्जनों किसानों को मौत के मुंह में पहुंचा दिया।

पंजाब सरकार ने भी ट्रिडेंट को भूमि देने के लिए किसानों पर लाठी बरसाने में कोताही नहीं बरती। दरअसल कॉरपोरेट और सरकार की मिली भगत के कारण किसानों को सीधे पलायन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अभी तक देश में इस बात पर कोई सहमति हीं नहीं बनी कि भूमि छीनने से पहले किसानों को पुनर्स्थापित कैसे किया जाए। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कंस्ट्रक्शन के एक पावर प्लांट के लिए वहां की सरकार ने सैकड़ों किसानों को उजाड़ दिया। जिस दिन इस कंपनी ने अएने मेगापावर प्लांट का भूमि पूजन किया उसी दिन आंध्रसरकार ने किसानों पर गोली चलाई।

उड़ीसा की निलयगिरि पहाड़ियों में बॉक्साइट की खनन के लिए आई ब्रिटेन की कपंनी वेदांता ने वायदा तो किया ग्रमीणों को लाभ देने का, लेकिन किया क्या? धीरे धीरे वहां के मूल आदिवासियों को ही वहां से भगाना शुरू कर दिया। वहां के आदिवासी न सिर्फ अपना जंगल और अपनी जमीन गंवाने लगे, बल्कि उनकी संस्कृति भी ग्रहण लग गया। बताते है कि वेदांता ने चुपके चुपके हजारों हेक्टेयर जंगल पर बुलडोजर चला दिया। यह तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने आदिवासियों और जंगल में रहने वाले लोगों की सुन ली नहीं तो निलयगिरि की पहाड़ी खोज का विषय रह जाती। अब ब्रिटिश सरकार समेत तमाम बहुराष्ट्रीय कंपनियां इस लामबंदी में लगी हैं कि किसी भी तरह उनके हित सधते रहे।

इतने ज्वलंत विषय होने बाद भी यह मुद्दा राजनीतिक समर्थन और विरोध का बन कर रह गया है। संसद में इस पर खूब हंगामे हो चुके है। सत्ता पक्ष भी किसानों पर हो रहे जुल्मों को लेकर घड़ियाली आसूं बहाते रहे हैं। मायावती हो या सोनिया गांधी मौखिक रूप से सबकी प्राथमिकता किसान हैं। फिर भी किसान बर्बाद हो रहे हैं। यह कम दुखद नहीं है कि 100 करोड किसानों के रहते हुए उनके पास सिर्फ 27 फीसदी भूमि का मालिकाना हक रह गया है। शेष सभी भूमि मोटे साहुकारों या निजी कंपनियों के हाथ चली गई हैं। क्या होगा इस देश का। ❑

स्वदेशी जागरण मंच की राष्ट्रीय परिषद बैठक दिनांक 9–10 अप्रैल, 2011 को चैन्नई में संपन्न हुई। राष्ट्रीय परिषद् की बैठक में तीन प्रस्ताव पारित किए गए। जिन्हें हम पाठकों की जानकारी के लिए यहां प्रस्तुत कर रहे हैं :– सं.

पारित प्रस्ताव – 1

जी.एम. फसलों, जीवों और उनसे बने खाद्य पदार्थों को प्रतिबंधित किया जाए

जी.एम. (आनुवंशिक रूप से परिष्कृत) फसलों, जीवों और उनसे बने खाद्य पदार्थों के कारण जन स्वास्थ्य एवं देष की जैविक संपदा के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। बिना किसी प्रभावी जैव सुरक्षा उपायों के इन फसलों एवं जीवों पर अनुसंधान एवं परीक्षण की अनुमति और इनसे बने खाद्य पदार्थों के लिए नियमन एवं नियंत्रण का पूर्ण अभाव गहरी चिंता का विषय है।

ऐसी जी.एम. फसलों एवं जीवों में परिवर्तन एवं उनसे सटे, इन फसलों की टर्मिनेटर प्रौद्योगिकी के माध्यम से स्ट्रेलाईजेषन से निकले पराग के संदर्भ में अन्य देषों में आवष्यक रक्षा उपाय, अनिवार्य शर्त है। लेकिन भारत में समान रूप से घातक टर्मिनेटर प्रौद्योगिकी को लागू किए जाने से किसानों को उनकी बीज संपदा से वंचित किया जा रहा है।

वास्तव में यह समझ के परे है कि भारत सरकार द्वारा 'स्टारलिंक मक्की' के एलर्जी प्रभावों एवं चूहों के गुर्दो एवं लीवर पर 'जी.एम. टमाटरों' के उपभोग के प्रभावों का संज्ञान क्यों नहीं लिया गया। यह भी समझ के परे हैं कि सरकार को कौन सी मजबूरी जी.एम. उत्पादों पर लेबलिंग करने एवं जिन देशों में वे उत्पाद प्रतिबंधित हैं, के नामों को उस लेबल पर लिखने से रोक रही है।

क्यों बी.टी. कपास के जहरीले पराग के प्रसार को रोकने और उसके ए.ए.डी. जीन के साथ जुड़कर सुपर कीट के प्रादुर्भाव को रोकने की किसी रणनीति के बिना बी.टी. कपास को अनुमति दे दी गई? क्यों सरकार बी.टी. बैंगन के असफल परीक्षण के बावजूद उसे अनुमति देने में जल्दबाजी दिखा रही है?

इन सभी सवालों से यह साबित हो जाता है कि यह सरकार जन स्वास्थ्य और हमारे पारंपरिक जैव संपदा के साथ खिलवाड़ कर रही है। इससे भी अधिक दुख का विषय यह है कि प्रस्तावित बायोटेक नियामक कानून में सरकार द्वारा यह प्रस्ताव किया गया कि जो व्यक्ति जी.एम. फसलों का विरोध करेंगे उन्हें दण्डित किया जायेगा। सरकार को यह ध्यान रखना चाहिए कि जैव प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल आतंकवादियों द्वारा एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। अमरीकी सरकार ने तो कृषि जैव आतंकवाद के खिलाफ 300 करोड़ डॉलर के बजट के साथ एक रक्षा कक्ष भी स्थापित किया है।

इन तथ्यों के आलोक में आनुवंषिक रूप से संशोधित (जी.एम.) किस्मों के खतरों के मद्देनजर स्वदेषी जागरण मंच सरकार से मांग करता है कि भारत में जी.एम. बीजों के उपयोग पर तुरंत प्रभावी प्रतिबंध लगाए। ❑

पारित प्रस्ताव – 2

परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की समीक्षा कर उसे प्रतिबंधित किया जाए

जापान में 11 मई 2011 को आयी भीषण सूनामी के कारण फूकूषीमा परमाणु संयंत्र की आपदा को आज जापान और विष्व में भारी संकट के रूप में देखा जा रहा है। फूकूशीमा संयंत्र में 6 परमाणु रिएक्टर हैं और वे सभी 'बी.डब्ल्यू.आर' प्रकार के हैं। 11 मार्च को आयी सूनामी ने इन परमाणु रिएक्टरों के शीतलन प्रणाली को पूरी तरह से ध्वस्त ही कर दिया है। इसके कारण रिएक्टर कोर में गर्मी बढ़ने के कारण विस्फोट हो रहे हैं, ईंधन छड़ों के क्षतिग्रस्त होने के कारण-आसपास के क्षेत्र में रेडियोधर्मी पदार्थ फैल रहे हैं। तुरंत आणविकी आपातकाल भी घोषित कर दिया गया। इस प्रतिबंधित क्षेत्र में उत्पादित दूध और अन्य खाद्य पदार्थों का सेवन न करने की चेतावनी दी गई है।

फुकुषीमा के आसपास का समुद्री पानी भी रेडियोधर्मिता से दूषित हो चुका है और समुद्री जीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। सूनामी के एक

महीने के बाद भी अधिकारी रिएक्टरों से रेडियोधर्मी पदार्थों के विकरण को रोकने में असफल हो रहे हैं। जापान अनुषासनयुक्त लोगों के साथ अत्यधिक विकसित देष है, इसके बावजूद आणविकी आपदा का सामना करने में वे असमर्थ हो रहे हैं।

फुकुषीमा आणविकी विध्वंस ने दुनिया को परमाणु संयंत्रों के सुरक्षा मानकों और आपदा प्रबंधन के संबंध में पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है। ऐसी परिस्थिति में भारत इससे अछूता नहीं रह सकता।

आज भारत में 19 परमाणु रिएक्टर कार्य कर रहे हैं। तारापुर के 2 रिएक्टरों को छोड़कर शेष सभी 'कंडू' प्रकार के पी. एच.डब्ल्यू.आर. रिएक्टर हैं। जिनकी क्षमता 4000 मेगावाट की है, जो हमारी कुल क्षमता का मात्र 4 प्रतिषत ही है।

प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यू.पी.ए. सरकार ने देष में आणविक ऊर्जा का अत्यंत महत्वकांक्षी कार्यक्रम बनाया है।

- विवादास्पद भारत–अमरीकी आणविक समझौता किया गया है जिसकी आई. ए.ई.ए. एवं आणविकी पूर्तिकर्ता समूह से मान्यता भी प्राप्त कर ली गई है। संसद में तमाम विरोधों के बावजूद न्यूनतम देनदारी बिल भी पारित करवा लिया गया है।
- भारत द्वारा वर्तमान में 4000 मेगावाट की आणविकी ऊर्जा क्षमता को 2030 तक बढ़ाकर 60000 मेगावाट तक बढ़ाने का महत्वकांक्षी लक्ष्य घोषित किया गया है। यानि मात्र 20 वर्षों में 15 गुणा।
- यह सब आयातित रिएक्टरों, आयातित यूरेनियम इंधन और आयातित प्रौद्योगिकी के द्वारा प्राप्त किया जायेगा।
- सरकार की महाराष्ट्र, पष्चिमी बंगाल, गुजरात, आंध्र प्रदेष और तमिलनाडू प्रत्येक राज्य में 10000 मेगावाट क्षमता वाले 5 आणविक ऊर्जा पार्क स्थापित करने की योजना है।
- आणविक रिएक्टरों से होने वाले खतरे केवल भुकम्प एवं सूनामी से ही नहीं बल्कि आतंकवाद से भी हैं। हमारे वर्तमान एवं भविष्य के रिएक्टरों की आतंकवाद से सुरक्षा हेतु हम कितने तैयार है?
- आणविक ऊर्जा मूल रूप से असुरक्षित है और उसमें सुरक्षा हेतु प्रयास होते हैं और यही सुरक्षा के उपाय जो बाहरी तौर पर लगाए जाते है आपदाओं का कारण बनते हैं। आणविक आपदा रेडियोधर्मिता का प्रसार करती है जो मानव जीवन के लिए कई पीढ़ियों तक हानिकारक रहती है। जल, भूमि और वायु सभी में इसका जहर फैल जाता है।
- एक परमाणु रिएक्टर 40 वर्षों की अधिकतम अवधि के लिए काम करता है। इसके बाद आने वाली पीढ़ियों पर इन मृत रिएक्टरों की रक्षा और उन्हें ठंडा रखने की जिम्मेदारी रहती है। क्या हम अपने बच्चों पर यह असहनीय बोझ नहीं डाल रहे हैं?
- हम देख चुके है कि किस प्रकार हमारी सरकारों ने भोपाल गैस त्रासदी के समय व्यवहार किया। उसके बाद वास्तविक अपराधियों को सरकारी गाड़ियों और वायुयान में पुलिस की सुरक्षा के तहत भागने में मदद की गई और हजारों असहाय लोगों और बच्चों को न्याय के बिना उसके परिणामों से भुगतने के लिए बिना आसरे छोड़ दिया गया।

स्वदेशी जागरण मंच की राष्ट्रीय परिषद यह मांग करती है कि –

1. परमाणु ऊर्जा के विस्तार कार्यक्रम को न्यूनतम 3 वर्ष के लिए स्थगित कर दिया जाए।
2. तीन वर्ष के इस कालखंड को परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की समीक्षा हेतु मानचित्र बनाने के लिए इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि आणविक ऊर्जा में निहित विध्वंसकारी नतीजों के मद्देनजर हम परमाणु ऊर्जा पर प्रतिबंध लगाने में सफल हो जाएं।
3. आणविक ऊर्जा के लिए आवंटित धनराषि को पवन, सौर, ज्वारीय एवं जैव इंधनों जैसे अक्षय ऊर्जा स्रोतो के विकास हेतु अनुसंधान करने के लिए उपयोग किया जाए। यह ऊर्जा स्थाई, विकेंद्रीकृत एवं पर्यावरण के अनुकूल होगी। हमें याद रखना होगा कि परमाणु ऊर्जा में भोपाल गैस त्रासदी जैसे विध्वंस को देष सहन नहीं कर पायेगा। ❑

भगवान् आपने–आपको उन्हें देते हैं जो कुछ भी बचाये बिना सर्वात्म–भाव से अंग–प्रत्यंग समेत अपने–आपको उनके हवाले कर देते हैं। उनके लिये है स्थिरता, प्रकाश, शक्ति, परम सुख, स्वतंत्रता, विशालता, ज्ञान की उत्तुंगता और आनन्द–पारावार।

– श्रीअरविन्द

पारित प्रस्ताव – 3

काले धन का राष्ट्रीयकरण हो

देष में भ्रष्टाचार को लेकर जनता के बीच असंतोष चरम पर है। आम जन हर हाल में भ्रष्टाचार से छुटकारा चाहता है। इसके लिए वह हर उस संगठन, व्यक्ति और विचार को अपना समर्थन देने के लिए तैयार है जो देश को भ्रष्टाचार मुक्त करने की मुहिम प्रारंभ करने के लिए आगे आ रहा हैं। जनता भ्रष्टाचार और घोटालों से इतनी त्रस्त हो गई है कि वह इस मामले पर सीधी लड़ाई के लिए भी तैयार है। जरूरत है इस जन आक्रोश को दिशा देने की। स्वदेशी जागरण मंच इस विषय पर लगातार अपने कार्यक्रमों और आंदोलनों के माध्यम से वातावरण तैयार करने में अपनी भूमिका निभाता रहा है। मंच के कार्यकर्ता स्थान–स्थान पर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं।

मंच न सिर्फ सरकारी विभागों और प्रषासन में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करवाने के लिए कृत संकल्प है, बल्कि विदेशी बैंकों में जमा देश की अघोषित संपत्ति को भारत लाने पर सरकार को विवष करने के लिए विभिन्न स्तरों पर चल रहे अभियानों को अपना समर्थन दे रहा है। चाहे वह जन जागरण का अभियान हो या फिर उपयुक्त कानून बनाने में सलाहकार की भूमिका हो, मंच हर हाल में काले धन को देष में लाने और उसका उपयोग देष की अर्थव्यवस्था के विकास कार्यों में लगवाने के लिए सरकार को बाध्य करने हेतु आंदोलन चला रहा है और उसे तेज करने की योजना बना रहा है। विभिन्न स्रोतों से यह तथ्य सामने आ रहे हैं कि कर मुक्त देशों में भारतीयों द्वारा कम से कम 80 लाख करोड़ रूपये जमा हैं, जो भ्रष्टाचार या अन्य गैर कानूनी स्रोतों से प्राप्त धन हो सकते हैं। यह राषि लगभग हमारे एक वर्ष के सकल घरेलू उत्पादन से भी अधिक है। बढ़ते भ्रष्टाचार के कारण सरकारी राजस्व को होने वाली भारी हानि के कारण न केवल सरकार को भारी ऋण लेना पड़ता है, अतिरिक्त मुद्रा का प्रसार भी होता है। जिसके कारण जनता भारी मुद्रा स्फीति एवं महंगाई के बोझ तले लगातार दबती जा रही है।

सरकार को हो रही राजस्व की हानि के कारण शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी आवष्यक सामाजिक सेवाओं पर सरकारी खर्च नहीं हो पाता। स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में आज हमारे देष में एक हजार में से 66 बच्चे अपना पांचवां जन्मदिन भी नहीं मना पाते। निरक्षता हमारे देष के आर्थिक विकास में सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है। देष में बड़े–बड़े भ्रष्टाचार के मामलों, 2जी स्पेक्ट्रम (1.76 करोड़), राष्ट्र मंडल खेल (50 हजार करोड़), तेलगी घोटाला (40 हजार करोड़) इत्यादि ने देष को अत्यंत भ्रष्ट देषों की श्रेणी में ला खड़ा किया है और आज देष का पारदर्षिता सूचकांक गिरकर 3.3 तक पहुंच गया है और देष भ्रष्टाचार की सीढ़ी पर 89वें स्थान पर पहुंच चुका है।

देष की जनता की मेहनत से कमाया हुआ धन या तो विदेषों को लाभ पहुंचा रहा है अथवा अनैतिक तरीके से देष में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। मंच का यह मानना है कि यदि यह धन देष में आ जाता है तो देष में किसी भी परियोजना के लिए अगले दस वर्ष तक सरकारों को किसी कर्ज की जरूरत नहीं होगी।

मंच सरकार के हर उस तर्क को खारिज करता है जिसमें यह कहा जा रहा है कि विभिन्न देषों के बीच हुए समझौते के कारण भारत स्विस बैंक या अन्य कर स्वर्ग देषों के बैंकों में जमा धन की जानकारी हमें नहीं मिल सकती या उन लोगों के नाम सामने नहीं आ सकते जिन्होंने इन देषों में भारत की संपत्ति को छुपा रखा है। मंच सरकार को यह चेतावनी देता है कि काले धन को देष में वापिस लाने के प्रयासों के साथ की साथ इसमें शामिल लोगों के नाम सार्वजनिक करे।

स्वदेषी जागरण मंच की यह राष्ट्रीय परिषद यह प्रस्ताव करती है कि सरकार शीघ्र ही देष को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए ऐसा कानून बनाए जिसमें यह प्रावधान हो कि भ्रष्टाचार के आरोपियों को बिना किसी देरी के सख्त सजा मिले। भ्रष्टाचार के आरोपियों को चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया जाए। आरोप सिद्ध होने पर भ्रष्टाचारियों की संपत्ति जब्त कर ली जाए।

राष्ट्रीय परिषद यह भी प्रस्ताव करती है कि विदेषों में जमा काले धन को सिर्फ कर चोरी के दृष्टिकोण से न देख कर देष के खिलाफ मामला माना जाए और काला धन जमा करने वालों पर देषद्रोह का मुकदमा चलाया जाए। इस प्रकार से विदेषों में गैर कानूनी रूप से जमा काले धन के मामलों और भ्रष्टाचार के मामलों में तीव्र न्याय मिलने के लिए समयबद्ध न्याय की प्रक्रिया अपनाए जाने संबंधित कानून बनें। स्रोत न बताने वालों के धन को जब्त कर लिया जाए और उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। ❑

खेती पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों की निगाहें

मोनसेंटो के समझौते में यह भी स्पष्ट है कि दोनों पक्ष इसे गुप्त रखेंगे व एक पक्ष दूसरे पक्ष की लिखित अनुमति के बिना किसी अन्य व्यक्ति या संगठन को इसकी जानकारी नहीं देगा। यानी करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाले समझौतों के बारे में यदि राजस्थान सरकार को अपने नागरिकों, किसानों व पंचायतों को जानकारी देनी हो तो उसे पहले मानसेंटो से लिखित अनुमति लेनी होगी। पंचायत प्रतिनिधियों के हालिया सम्मेलन में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया गया कि इन समझौतों में थोड़े बहुत बदलाव से कुछ हासिल नहीं होगा। जरूरत है इन्हें पूरी तरह रदद कर सरकारी तंत्र सीधे किसानों की सहायता करे।

■ भारत डोगरा

गौरतलब है कि इस समय बीटी काटन के अतिरिक्त अन्य जीएम फसलों को भारत में स्वीकृति नहीं मिली है पर स्वीकृति दिलाने के बहुत ताकतवर उच्च स्तरीय प्रयास अंदरखाने चल रहे बताये जाते हैं। बहुत ऊपर तक के तंत्र को इसके लिए प्रभावित किया जा रहा है। यदि इन तिकड़मों से अन्य जीएम फसलों को स्वीकृति मिल गई तो जिस तरह का जाल राजस्थान सरकार के इन समझौतों ने फैलाया है, उससे जीएम फसलों को देश में बहुत तेजी से फैलाने में मदद मिलेगी।

बीते आठ अप्रैल को जयपुर में राजस्थान के 14 जिलों से आये पंचायत प्रतिनिधियों, विशेषकर महिलाओं व सामाजिक कार्यकर्ताओं ने राजस्थान सरकार द्वारा सात बहुराष्ट्रीय कंपनियों व अन्य बड़ी कंपनियों के साथ बीज व कृषि अनुसंधान के संबंध में किये गये समझौतों के विरुद्ध आवाज उठाई।

राजस्थान समग्र सेवा संगठन व अलगी (दिल्ली) द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में कहा गया कि इन समझौतों से राजस्थान की खेती–किसानों के लिए बहुत खतरा है और इन्हें सीधे रद्द किया जाना चाहिए। राजस्थान सरकार ने कृषि क्षेत्र में मोनसेंटो कंपनी के साथ बहुपक्षीय सहयोग संबंधी समझौता किया है और इसी तर्ज पर पांच–छह अन्य कंपनियों से भी समझौते हुए हैं। समझौतों के जरिए इन कंपनियों को राजस्थान की अधिकांश खाद्य, चारा व व्यापारिक फसलों के बीज उत्पादन, वितरण, अनुसंधान, जानकारी के प्रसार, फसल की कटाई की तकनीक आदि क्षेत्रों में महवपूर्ण स्थान और लाभ मिल सकता है। इनमें से अधिकांश कंपनियां बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्र की अग्रणी पंक्ति में शुमार हैं।

यह विज्ञान का वह क्षेत्र है जो अन्य कायरे के अतिरिक्त जी एम कंपनियों के प्रसार से भी जुड़ा है। गौरतलब है कि इस समय बीटी काटन के अतिरिक्त अन्य जीएम फसलों को भारत में स्वीकृति नहीं मिली है पर स्वीकृति दिलाने के बहुत ताकतवर उच्च स्तरीय प्रयास अंदरखाने चल रहे बताये जाते हैं। बहुत ऊपर तक के तंत्र को इसके लिए प्रभावित किया जा रहा है। यदि इन तिकड़मों से अन्य जीएम फसलों को स्वीकृति मिल गई तो जिस तरह का जाल राजस्थान सरकार के इन समझौतों ने फैलाया है, उससे जीएम फसलों को देश में बहुत तेजी से फैलाने में मदद मिलेगी।

अतः इन समझौतों में जो लिखा गया है, उसके साथ हमें बहुराष्ट्रीय

कंपनियों के खाद्य व कृषि व्यवस्था को नियंत्रित करने व इसके लिए जीएम तकनीक का उपयोग करने के प्रयासों को ध्यान में रखना पड़ेगा। समझौतों से ऐसी तैयारी होगी कि जैसे ही जीएम फसलों की मंजूरी मिले वैसे ही इन्हें तेज़ी से फैलाया जा सके। इसके अतिरिक्त जीएम फसल संबंधी प्रयोग की अधिक सुविधाएं भी इस तरह के समझौतों से प्राप्त हो सकती हैं। इनके कारण सरकार व कृषि विश्वविद्यालयों का अनुसंधान तंत्र भी इन कंपनियों के खिलवाड़ का स्थान बन जाएगा। ध्यान रखना जरूरी है कि जीएम फसलों का थोड़ा बहुत प्रसार व परीक्षण भी बहुत घातक हो सकता है।

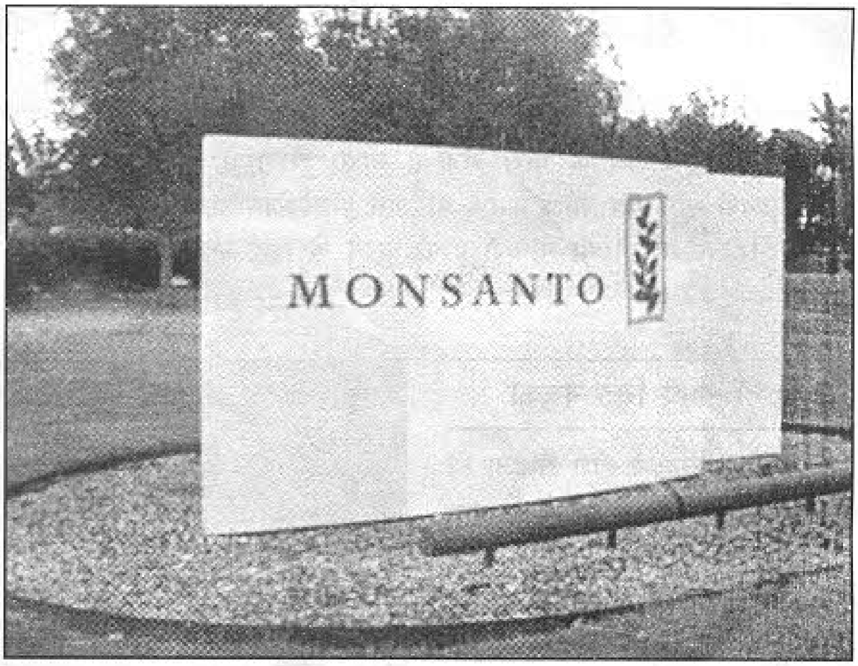

मूल मुद्दा यह है कि इनसे जो सामान्य फसलें हैं वे भी कुप्रभावित या प्रदूषित हो सकती हैं। यह जेनेटिक प्रदूषण बहुत तेजी से फैल सकता है और इस कारण जो क्षति होगी, उसकी भरपाई नहीं हो सकती। विश्व व राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त जानकारी यही बताती है कि बहुराष्ट्रीय बीज कंपनियों व उनके सहयोगियों पर सरकार को बहुत निगरानी रखने की जरूरत है। वहां इन समझौतों को लागू किया गया तो सरकारी कृषि अधिकारी व इन कंपनियों के अधिकारी बार–बार एक मंच पर, एक साथ काम करते हुए नजर आएंगे व उनमें भेद करना कठिन हो जाएगा। सरकारी तंत्र को प्रभावित करने का इन कंपनियों को भरपूर अवसर मिलेगा। मोनसेंटो के अधिकारियों व विशेषज्ञों को सरकार लैक्चर के लिए बुलाएगी तो कृषि अधिकारियों, विद्यार्थियों, वैज्ञानिकों आदि को मोनसेंटो के फार्मों में घुमाया जाएगा और प्रशिक्षण दिया जाएगा।

सरकार मोनसेंटो को न केवल अपनी विभिन्न अनुसंधान सुविधाएं उपलब्ध करवाएगी अपितु भूमि भी उपलब्ध करवाएगी और पूंजी सब्सिडी भी देगी। अधिक व्यापक स्तर पर समझौते में कहा गया है कि निजी क्षेत्र को आकर्षित करने के लिए सरकार उसके अनुकूल नियम व नीतियां बनाएगी। समझौते में यह भी कहा गया है कि कंपनी मशीनों से फसल की कटाई के तरीके विकसित करेगी व ऐसी मशीनें उपलब्ध करवाएगी। मशीनीकृत कटाई का मजदूरों पर क्या असर होगा, उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है।

मोनसेंटो के समझौते में यह भी स्पष्ट है कि दोनों पक्ष इसे गुप्त रखेंगे व एक पक्ष दूसरे पक्ष की लिखित अनुमति के बिना किसी अन्य व्यक्ति या संगठन को इसकी जानकारी नहीं देगा। यानी करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाले समझौतों के बारे में यदि राजस्थान सरकार को अपने नागरिकों, किसानों व पंचायतों को जानकारी देनी हो तो उसे पहले मानसेंटो से लिखित अनुमति लेनी होगी। पंचायत प्रतिनिधियों के हालिया सम्मेलन में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया गया कि इन समझौतों में थोड़े बहुत बदलाव से कुछ हासिल नहीं होगा। जरूरत है इन्हें पूरी तरह रद्द कर सरकारी तंत्र सीधे किसानों की सहायता करे। ❑

मूल मुद्दा यह है कि इनसे जो सामान्य फसलें हैं वे भी कुप्रभावित या प्रदूषित हो सकती हैं। यह जेनेटिक प्रदूषण बहुत तेजी से फैल सकता है और इस कारण जो क्षति होगी, उसकी भरपाई नहीं हो सकती। विश्व व राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त जानकारी यही बताती है कि बहुराष्ट्रीय बीज कंपनियों व उनके सहयोगियों पर सरकार को बहुत निगरानी रखने की जरूरत है। वहां इन समझौतों को लागू किया गया तो सरकारी कृषि अधिकारी व इन कंपनियों के अधिकारी बार–बार एक मंच पर, एक साथ काम करते हुए नजर आएंगे व उनमें भेद करना कठिन हो जाएगा।

गांव से शहर की ओर पलायन के कारण एवं निवारण

भारत पर 1000–1200 सालों के परकीय आक्रमण व शासन व्यवस्था ने भारत की इस स्वर्णिम व्यवस्था को चरमरा दिया। लगान व कर के भारी बोझ ने भारत के गांवों की व्यवस्था को लड़खड़ा दिया। कृषि व व्यवसाय को अलाभकारी मान कर लोग उससे पलायन करने लगे तथा परकीय लोगों की शासन–व्यवस्था के अंग बनने के लिए छोटी से छोटी भी नौकरी प्राप्त करने के लिए लालायत होने लगे। गांव का स्वावलंबी भाव समाप्त होने लगा. . .

■ डॉ. नन्द सिंह नरूका

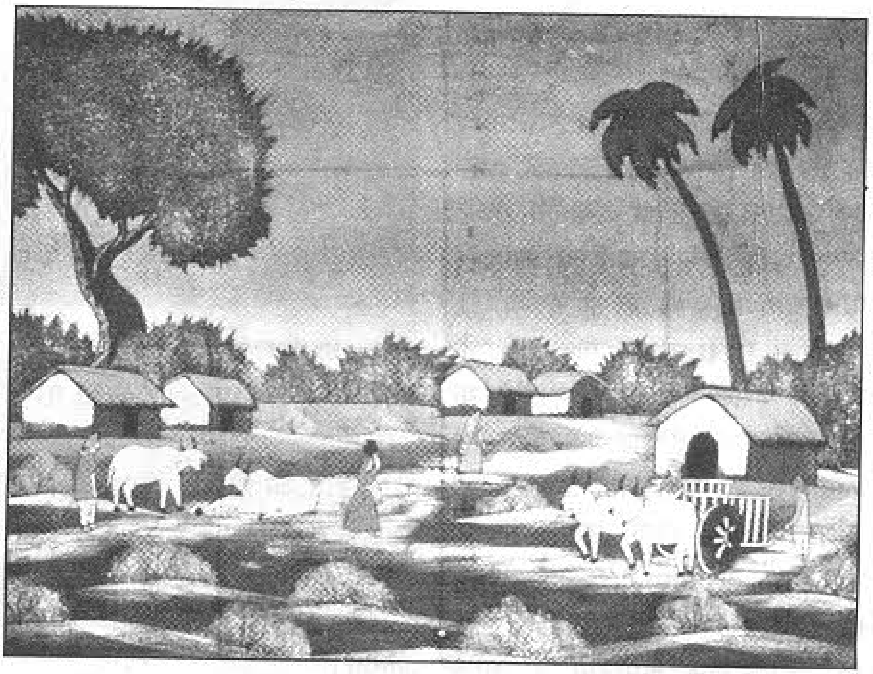

मानव ने जब से होश संभाला था तभी से वह भोजन की तलाश में तथा सुरक्षा के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता रहा है। मानव की बढ़ती संख्या सुविधापूर्ण जीवन यापन के संसाधन तथा सुरक्षा के भाव ने मानव के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को प्रेरित किया। पलायन का यह सिलसिला लगातार चलता रहा है। पलायन से सुरक्षा एवं सभ्यता को जब खतरा होने लगा तो वह सोचने को मजबूर हुआ। आज इसी को ध्यान में रखकर विचार करने की आवश्यकता है।

भारत को गांवों का देश कहा जाता है। भारत की सभ्यता एवं संस्कृति का विकास भी शहर के साथ–साथ गांवों में भी समानरूप से पल्लवित एवं पुष्पित रहा प्रत्येक गांव स्वावलंबन की एक इकाई रहा है। आवश्यकता की सभी वस्तुएं एवं सेवाओं की आपूर्ति गांव में ही प्राप्त हो जाती थी। समाज के सभी लोग अपने–अपने रीति–रिवाजों को हिल मिलकर मनाते रहे हैं।

भारत को गांवों का देश कहा जाता है। भारत की सभ्यता एवं संस्कृति का विकास भी शहर के साथ–साथ गांवों में भी समानरूप से पल्लवित एवं पुष्पित रहा प्रत्येक गांव स्वावलंबन की एक इकाई रहा है। आवश्यकता की सभी वस्तुएं एवं सेवाओं की आपूर्ति गांव में ही प्राप्त हो जाती .थी। समाज के सभी लोग अपने–अपने रीति–रिवाजों को हिल मिलकर मनाते रहे हैं। आर्थिक विषमता नहीं थी। किसान की उपज में सभी कामगारों का हिस्सा होता था। सामूहिक चौपाल, धर्मशाला, पनघट, प्याऊ का निर्माण एवं संचालन होता था। न्याय व रक्षा व्यवस्था की समुचित व्यवस्था रहती थी। सुख दुख में भी सभी की सामूहिक भागीदारी होती थी। ऐसे स्वावलंबी गांवों के कारण ही भारत सोने की चिड़िया कहलाता रहा। अन्न, पशुधन की पर्याप्तता के कारण ही यह देश घी, दूध की नदियां बहती थी ऐसा कहा जाता रहा। चिकित्सा एवं शिक्षा की व्यवस्था समाज स्वयं करता था अतः लोग शिक्षित दीक्षित तो थे ही स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बलशाली एवं कठोर परिश्रमी हुआ करते थे।

भारत पर 1000–1200 सालों के परकीय आक्रमण व शासन व्यवस्था ने

भारत की इस स्वर्णिम व्यवस्था को चरमरा दिया। लगान व कर के भारी बोझ ने भारत के गांवों की व्यवस्था को लड़खड़ा दिया। कृषि व व्यवसाय को अलाभकारी मान कर लोग उससे पलायन करने लगे तथा परकीय लोगों की शासन–व्यवस्था के अंग बनने के लिए छोटी से छोटी भी नौकरी प्राप्त करने के लिए लालायत होने लगे। गांव का स्वावलंबी भाव समाप्त होने लगा अंग्रेजों के आने के बाद तो उनके द्वारा स्थापित कल कारखानों के लिए कच्चे माल की आपूर्त्ति तक हम सीमित हो गए तथा तैयार माल महंगे दामों पर खरीद कर प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से इंग्लैंड को विकसित तथा भारत को अविकसित करते रहे। गांवों में रोजगार का अभाव होता गया तथा नौकरी एवं रोजगार की तलाश में लोग शहर की ओर पलायन करने लगे। आजाद भारत में भी गांव, कृषि, ग्राम रोजगार, स्वावलंबन की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया जिसके फलस्वरूप काफी मात्रा में गांवों से शहरों की ओर पलायन होने लगा।

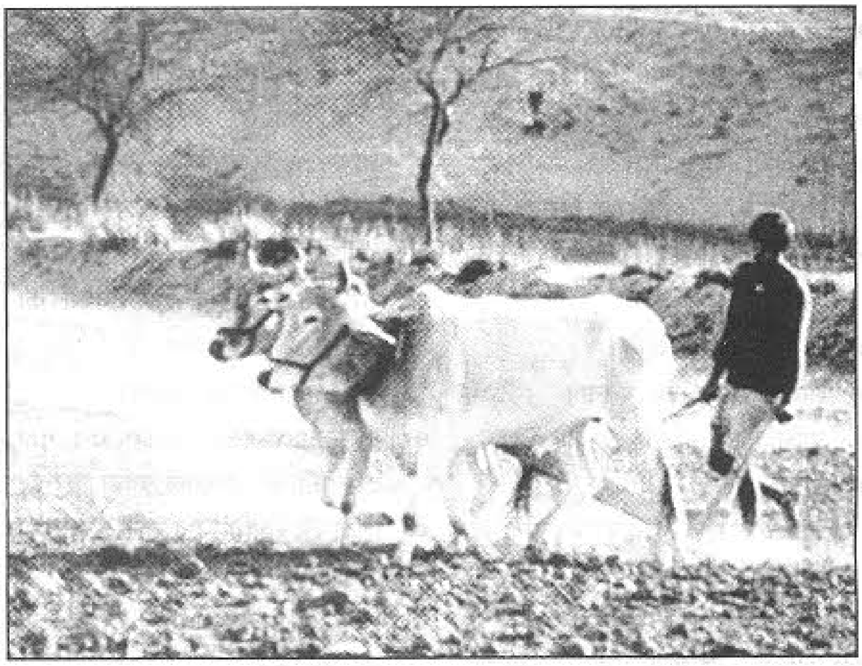

स्थान का महत्व, सुविधा, जलवायु, जल–आपूर्त्ति, भूमि की उपजता, खनिज की उपलब्धता, ईंधन की उपलब्धता, यातायात के साधनों की उपलब्धता, आर्थिक प्रगति, धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक परंपरा, कानून, सरकारी नीतियां, राजनैतिक स्थिरता आदि कारण किसी स्थान की ओर जनसंख्या के पलायन के आधार हुआ करते है। स्वतंत्रता के समय जहां भारत की लगभग 80 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती थी वह 2001 की जनगणना के अनुसार 72 प्रतिशत रह गयी।

पलायन के प्रमुख कारण :–

- गांव में पर्याप्त रोजगार का अभाव।
- सीमित कृषि जोत।
- पशुधन पालन में कठिनाई।
- परंपरागत धंधों का आधुनिक कल कारखानों से प्रतिस्पर्धा।
- शिक्षा की समुचित व्यवस्था का अभाव।
- चिकित्सा सुविधाओं का अभाव।
- परिवहन साधनों एवं मार्गों का अभाव।
- ऊर्जा के साधनों यथा विद्युत/शक्ति/ईंधन आदि का अभाव।
- सामाजिक समरसता का अभाव।
- आधुनिक सुविधाओं का अभाव।
- पानी की सुविधा का अभाव आदि।

शहरीकरण की समस्याएं :–

- जनसंख्या का अत्यधिक दबाव।
- अपराध–वृत्ति में वृद्धि, माफिया सरगना।

अंग्रेजों के आने के बाद तो उनके द्वारा स्थापित कल कारखानों के लिए कच्चे माल की आपूर्त्ति तक हम सीमित हो गए तथा तैयार माल महंगे दामों पर खरीद कर प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से इंग्लैंड को विकसित तथा भारत को अविकसित करते रहे। गांवों में रोजगार का अभाव होता गया तथा नौकरी एवं रोजगार की तलाश में लोग शहर की ओर पलायन करने लगे। आजाद भारत में भी गांव, कृषि, ग्राम रोजगार, स्वावलंबन की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया जिसके फलस्वरूप काफी मात्रा में गांवों से शहरों की ओर पलायन होने लगा।

- बढ़ता शोरगुल, ध्वनि प्रदूषण।
- पर्यावरण प्रदूषण।
- गंदे नाले।
- अपशिष्ट का फैलाव।
- बिमारियों व तनाव का बढ़ना।
- कच्ची बस्ती, झुग्गी झोंपड़ियों का निर्माण।
- आत्मीयता की कमी।
- शोषण प्रवृत्ति का बढ़ना।
- आर्थिक असमानता में वृद्धि।
- नैतिक मूल्यों में गिरावट।

भारत जब तक स्वावलंबी गांवों का देश रहा तब तक भारत विश्व में शिरमोर रहा। भारत में पर्याप्त खनिज पदार्थ हैं सभी ऋतुओं का बारी–बारी से आगमन होता हैं सामान्य शिष्टाचार एवं नैतिक मूल्यों का पोषण होता रहा है। अपने इस देश को खोई हुई पुरानी पुनः दिलानी है तो गांवों की ओर पर्याप्त ध्यान देना होगा तथा आधुनिक सभी सुविधाओं, तकनीकों से गांवों को लाभान्वित करना होगा।

गांवों से शहर की ओर पलायन रोकने के लिए निम्न प्रस्तावित कार्यों की ओर ध्यान देना लाभकारी होगा।

- कृषि को उद्योग का दर्जा देकर पल्लवित व विकसित करना।
- परंपरागत धंधों को संरक्षण प्रदान कर उनके उत्पाद एवं सेवाओं का उपयोग बढ़ाना तथा उन्हें पर्याप्त पारिश्रमिक प्रदान करना।
- नए–नए रोजगार सृजित कर गांव के लोगों को रोजगार प्रदान करना।
- शिक्षा की समुचित एवं स्तरीय व्यवस्था करना।
- चिकित्सा की आधुनिक सुविधाओं का सन्निकटन।
- यातायात के पर्याप्त साधनों तथा पक्की सड़कों की समुचित व्यवस्था करना।
- विद्युत एवं ईंधन की व्यवस्था।
- पानी की व्यवस्था, पेय स्रोत का विकास।
- भवन निर्माण एवं नाली निर्माण को बढ़ावा।
- गोचर भूमि की सुरक्षा, पशुधन के संरक्षण की आधुनिकतम व्यवस्था।
- सामुदायिक केन्द्रों, बागानों की व्यवस्था।
- सुरक्षा व न्याय व्यवस्था स्थानीय स्तर पर करना।

हममें से अधिकांश लोग गांवों से है और शहर में आकर बस गए हैं। अत्याधुनिक सुविधाओं के प्रलोभन से हम शहर में रह रहे हैं परंतु अपनेपन का अभाव खलता है आज यदि उपरोक्त सभी सुविधा, व्यवस्था गांव में ही मिलने लग जाए या पास में ही मिल जाए जहां से गांव में आया जाया जा सकता है तो हम भी जहां गांव में हमारी आत्मा बसती है, रहना पसंद करेंगे और शहर की भागम–भाग जिंदगी से दूर तनाव रहित वातावरण में गांव में रहना पसंद करेंगे, काश ये सभी हो! ❑

:: सूचना ::

स्वदेशी पत्रिका सम्राज्यवाद के खिलाफ एक सशक्त आवाज है। पत्रिका को ऐसे लोगों से प्रतिक्रियाएं, रिपोर्ट या आलेख की अपेक्षा है जो राष्ट्रहित में सोचते हैं और देश के स्वावलम्बन के लिए कुछ करने की इच्छा रखते है। जरूरी नहीं कि आप पत्रकार या लेखक ही हों, अपने आस–पास से जुड़ी चीजों के प्रति आपकी संवदेना है और आप शब्दों में उसे लिख सकते है तो हमें अवश्य लिख भेजें। साथ ही स्वदेशी पत्रिका में छपे लेख आपको कैसे लगते हैं, क्या आप इसमें कुछ नए विषयों का समायोजन चाहते हैं कृपया हमें अवश्य अवगत कराएं। आपके विचारों को हम प्राथमिकता के साथ प्रकाशित करने का भी प्रयास करेंगे।

हमारा पता है :–

संपादक

स्वदेशी पत्रिका

'धर्मक्षेत्र', सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

बढ़ती आबादी, बढ़ता खाद्य संकट

बढ़ती जनसंख्या के परिप्रेक्ष्य में हमें आम आदमी के लिए उसकी क्रय शक्ति के अनुरूप रोटी की उपलब्धता संबंधी चुनौतियों को ध्यान में रखना होगा। इस हेतु आजादी के बाद उत्तरी राज्यों में कृषि संबंधी शोध तथा बेहतर तकनीक के ईजाद के लिए गठित मृतप्राय हो चुकी सरकारी एक्सटेंशन एजेंसियां पुनर्जीवित करनी होंगी. . .कृषि शिक्षा, रासायनिक खाद के स्वरूप, गुण–दोष और गलत प्रयोग के खतरों से संबंधित उपयोगी जानकारियां पहुंचानी होंगी। देश की मंडियों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की खाद्यान्न संबंधी खुली खरीद को नियंत्रित करना होगा। किसानों को बैंकों से आसानी से कर्ज मिले। ग्रामीण क्षेत्रों में लघु सिंचाई योजनाओं को बढ़ावा दिया जाए। कुल मिलाकर बढ़ती जनसंख्या के लिए खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के हरसंभव प्रयासों के साथ जनसंख्या नियंत्रण के बारे में भी गंभीरता से सोचना होगा।

पिछले एक दशक में देश में 18.1 करोड़ नई आबादी जुड़ गई है। जहां दुनिया की कुल आबादी में भारत की हिस्सेदारी 17.5 फीसद है वहीं पृथ्वी के कुल धरातल का मात्र 2.4 फीसद हिस्सा ही उसके पास है। अमेरिकी एजेंसी पॉपुलेशन रेफरेंस ब्यूरो के अनुसार 2050 में भारत की जनसंख्या चीन को पीछे छोड़ सर्वाधिक 162.8 करोड़ के आसपास हो जाएगी। तेजी से बढ़ती जनसंख्या देश के आर्थिक–सामाजिक विकास के लिए खतरे की घंटी है। चिंताजनक है कि इस समय देश की एक तिहाई आबादी भूख के साये में आगे बढ़ रही है। बढ़ती जनसंख्या के कारण गरीबी और भूख की समस्या मिटाने के सारे लक्ष्य फेल हो रहे हैं। चूंकि गरीब परिवारों में जन्मदर मध्य व उच्च वर्ग से बहुत अधिक है और उनके पास आगे बढ़ने के संसाध न कम हैं अतः गरीब वर्ग का विस्तार होता जा रहा है।

स्पष्ट है कि देश में बढ़ती जनसंख्या के हिसाब से अनाज की मांग बढ़ रही है। 2010–11 में 23.58 करोड़ टन अनाज उत्पादन हुआ है और 2020 तक देश के लिए 36 करोड़ टन अनाज की आवश्यकता पड़ेगी जिसे उत्पादित करना चुनौतीपूर्ण होगा। इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल रिलेशन के अनुसार

■ जयंतीलाल भंडारी

भारत में खाद्यान्न उत्पादकता घटने, ग्लोबल वार्मिंग, मानसून के धोखे, बायोडीजल के लिए अनाज का उपयोग और मोटे अनाज को बढ़ावा न देने के कारण 2011 के बाद (23 करोड़ 30 लाख) है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन और विकसित देशों के आर्गेनाइजेशन फार इकोनामिक आपरेशन एंड डेवलपमेंट के संयुक्त अध ययन में कहा गया है कि विकसित देशों की अपेक्षा भारत जैसे विकासशील

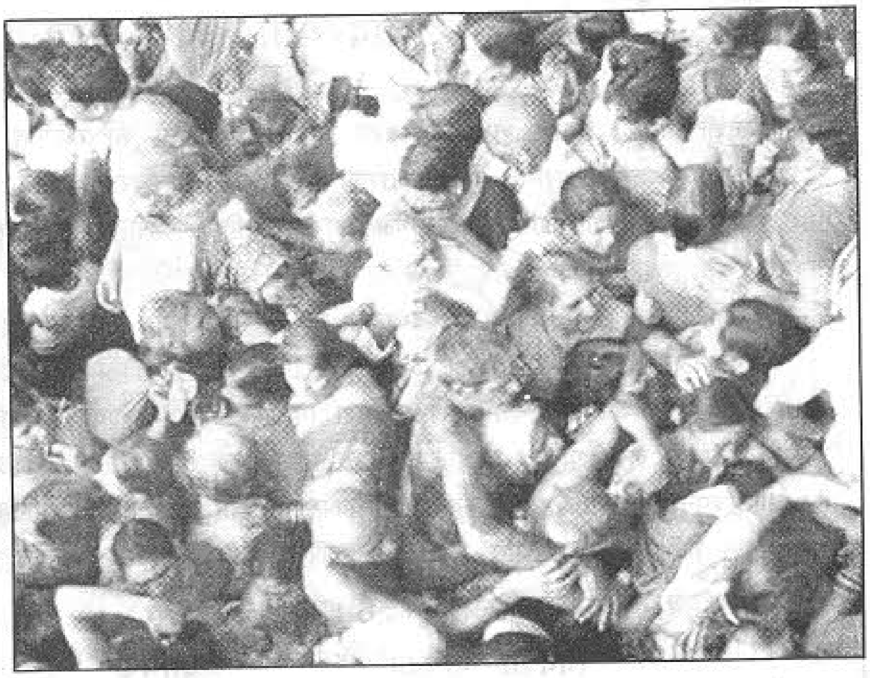

देश में सभी के लिए भोजन जुटाना और कठिन हो जाएगा।

संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन (यूएनएफएओ) की रिपोर्ट के अनुसार पर्याप्त खाद्यान्न के अभाव में भारत में भूख और कुपोषण की समस्या बढ़ रही है। यहां भूख और कुपोषण से प्रभावित लोगों की संख्या विश्व में सबसे अधिक

देशों में खाद्यान्न परिदृश्य पर चिंता बढ़ गई है।

खाद्यान्न के लिए विश्व बाजार पर विकाशशील देशों की निर्भरता में वृद्धि होगी और कीमतों में वृद्धि से जन जीवन प्रभावित होने की आशंका है। इसमें दो राय नहीं कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनाज की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं।

पिछले तीन सालों में दुनिया में खाद्य सामग्रियों के दुगुने बढ़े दामों के कारण भूखों तक अनाज नहीं पहुंच रहा है। बढ़ती जनसंख्या के कारण खाद्यान्न की मांग पूरा करने के लिए कृषि वृद्धि दर बढ़ाने की जरूरत है।

आंकड़े बताते हैं कि पहली पंचवर्षीय योजना यानी 1950–51 से लेकर 2010–11 तक जीडीपी की वृद्धि दर 300 प्रतिशत रही लेकिन कृषि क्षेत्र की सिर्फ 75 प्रतिशत। यानी कृषि क्षेत्र में एक और हरित क्रांति की जरूरत है। इसके तहत कृषि भूमि की उत्पादकता बढ़ाने के साथ खेती में लगे प्रति व्यक्ति की उत्पादन क्षमता बढ़ाए जाने का प्रयास होना चाहिए। इसके लिए आधारभूत सुविधाएं मजबूत बनाने की जरूरत है। सबसे जरूरी है बिजली और सड़क–व्यवस्था दुरुस्त करना। साथ ही कृषि उत्पादों की सप्लाई चेन, मार्केटिंग और विपणन आदि को आधुनिक बनाया जाना जरूरी है।

बढ़ती जनसंख्या के परिप्रेक्ष्य में हमें आम आदमी के लिए उसकी क्रय शक्ति के अनुरूप रोटी की उपलब्धता संबंधी चुनौतियों को ध्यान में रखना होगा। इस हेतु आजादी के बाद उत्तरी राज्यों में कृषि संबंधी शोध तथा बेहतर तकनीक के ईजाद के लिए गठित मृतप्राय हो चुकी सरकारी एक्सटेंशन एजेंसियां पुनर्जीवित करनी होंगी। किसानों तक हरित क्रांति विषयक नये शोध, वैज्ञानिक विचार और तकनीक पहुंचानी होगी। उन तक कृषि शिक्षा, रासायनिक खाद के स्वरूप, गुण–दोष और गलत प्रयोग के खतरों से संबंधित उपयोगी जानकारियां पहुंचानी होंगी। देश की मंडियों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की खाद्यान्न संबंधी खुली खरीद को नियंत्रित करना होगा। किसानों को बैंकों से आसानी से कर्ज मिले। ग्रामीण क्षेत्रों में लघु सिंचाई योजनाओं को बढ़ावा दिया जाए। कुल मिलाकर बढ़ती जनसंख्या के लिए खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के हरसंभव प्रयासों के साथ जनसंख्या नियंत्रण के बारे में भी गंभीरता से सोचना होगा। ❑

सदस्यता संबंधी सूचना

मान्यवर,

स्वदेशी पत्रिका आज देश में चल रहे स्वदेशी आंदोलनों का स्थापित प्रतीक बन चुकी है। पिछले कई वर्षों से स्वदेशी पत्रिका ने असंगत एवं एकतरफा वैश्वीकरण, जनविरोधी आर्थिक उदारीकरण के विरोध एवं वैकल्पिक और रचनात्मक स्वदेशी आंदोलन के पक्ष में एक सक्रिय प्रहरी के नाते हमेशा आपको जागरूक बनाया है एवं आपसे संवाद स्थापित किया है। विगत कालखंड में इन सभी मुद्दों पर हमें आप जैसे सजग पाठकों का अपेक्षित सहयोग भी मिलता रहा है और भविष्य में भी मिलेगा ऐसा, विश्वास है।

आपसे आग्रह है कि स्वदेशी पत्रिका की आपकी सदस्यता अवधि यदि समाप्त हो गई हो तो कृपया पिछले समय से आगामी वर्ष तक की राशि धनादेश (मनीआर्डर), चेक एवं मांग पत्र (डिमांड ड्राफ्ट) के माध्यम से शीघ्र भेजने की कृपा करें। पत्रिका के लिफाफे के उपर चिपकाए गए पते की प्रथम पंक्ति में सदस्यता अवधि अंकित है। आप अपनी सदस्यता राशि ''स्वदेशी पत्रिका'' के नाम पत्रिका के कार्यालय के पते पर भेज सकते हैं। सदस्यता अद्यतन न हो पाने की स्थिति में वित्तीय कारणों से पत्रिका आगे जारी रखना कठिन होगा।

सदस्यता शुल्क निम्न प्रकार है।

स्वदेशी पत्रिका	वार्षिक	आजीवन
हिन्दी	100/–	1000/–
अंग्रेजी	100/–	1000/–

हमें आपका सहयोग स्वदेशी आंदोलन को राष्ट्रव्यापी एवं जनोन्मुखी बनाने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। कृपया स्वदेशी पत्रिका स्वयं भी पढ़ें एवं अन्य को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। पत्रिका के संबंध में अपना निष्पक्ष विचार हमें अवश्य भेजें।

पता : **स्वदेशी पत्रिका कार्यालय, 'धर्मक्षेत्र' शिव शक्ति मंदिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली–22**

शून्य सहनशीलता का सच

समाज में पैदा हुई अन्य विकृतियों की तरह ही भ्रष्टाचार भी हमारी एक खास मानसिकता के कारण पैदा हुआ है। सनातन परंपराओं से हमें जो मूल्य मिले हैं, उसके अनुरूप जब तक हम समष्टि के लिए जागृत नहीं होंगे तब तक सामाजिक बुराइयों का खात्मा भी कठिन है। समाज में आए इस पतन के लिए मैकाले–मार्क्स के मानसपुत्रों द्वारा पोषित शिक्षण व्यवस्था भी कसूरवार है, जिसने धीरे–धीरे सामाजिक मर्यादा का तानाबाना ही ध्वस्त कर डाला।

■ बलवीर पुंज

पिछले दिनों सिविल सेवा अधिकारियों के सम्मेलन में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने स्वीकार किया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता के सब्र का बांध टूट चुका है और अब वह ठोस कार्रवाई चाहती है। इसे एक ईमानदार, किंतु बेबस प्रधानमंत्री का मूक रोदन नहीं तो और क्या कहें? जुलाई, 2008 में विश्वासमत प्राप्त करने के लिए सांसदों की खरीद–फरोख्त से लेकर 2–जी स्पेक्ट्रम घोटाला, अंतरिक्ष घोटाला और राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन में सरकारी स्तर पर मचाई गई लूट के वह मूकदर्शक बने रहे। नेता प्रतिपक्ष की आपत्तियों को नजरअंदाज कर केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के पद पर एक दागदार व्यक्ति को नियुक्त उन्होंने किया। सत्तासुखभोग के लिए दूरसंचार मंत्री को संप्रग की दूसरी पारी में भी लूट मचाने की छूट उन्होंने दी।

प्रधानमंत्री ने देश से वादा किया था कि सत्ता में वापस आने पर देश से लूटकर बाहर ले जाए गए धन को कांग्रेस वापस लाएगी, किंतु क्या यह सच नहीं है कि कांग्रेसनीत सरकार अपनी दूसरी पारी में भी काले धन के संदर्भ में तब तक सोती रही, जब तक सर्वोच्च न्यायालय ने उसे कड़ी फटकार नहीं लगाई? सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद सरकार ने देश के सबसे बड़े टैक्स चोर हसन अली पर कार्रवाई करने की पहल की है, किंतु जिस हसन अली के अवैध कारनामों की खबर प्रवर्तन निदेशालय को सन 2007 में ही लग चुकी थी उसे किसके संरक्षण में इतने वर्षों तक इस अवैध कारोबार को चलाए रखने का अभयदान दिया गया?

काले धन की वापसी को लेकर सरकार की अब तक की तत्परता केवल एक आदमी हसन अली तक ही सीमित है। काले धन के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र द्वारा छेड़ी गई मुहिम में जहां दुनिया भर के 128 देश रजामंद हैं, वहीं 14 देश इस संधि से अलग हैं, जिनमें भारत भी एक है। क्यों? हसन अली ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की जा रही पूछताछ में अपने गोरखधंधे के साथी, महाराष्ट्र के तीन नामचीन कांग्रेसी नेताओं के शामिल होने का खुलासा किया है।

वे कौन हैं? प्रधानमंत्री इन तमाम विरुपताओं के मूकदर्शक हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ जनाक्रोश को उचित ठहराने वाले प्रधानमंत्री को यह भी बताना चाहिए कि जिस लोकपाल बिल को जल्द से जल्द पारित कराने का समर्थन वह कर रहे हैं उसी लोकपाल बिल की राह में दिन–प्रतिदिन नए–नए अवरोध खड़े करने वाले कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ उन्होंने मौन क्यों साध रखा है? अन्ना हजारे की प्रारूप समिति में संविधानेत्तर लोगों के शामिल होने का आरोप लगाने वाले कांग्रेसियों के मौन समर्थन में खड़े प्रधानमंत्री यह बताएं कि संप्रग समन्वय समिति की अध्यक्षा के नाते सोनिया गांधी का सत्ता अधिष्ठान पर हावी हो जाना कहां तक

संविधान सम्मत है?

भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे के नेतृत्व में किए गए आंदोलन को जनता का व्यापक समर्थन मिलना वस्तुतः ऐसे दोहरे मापदंडों के प्रति जनता के आक्रोश को ही रेखांकित करता है। भ्रष्टाचार का एक आयाम यह भी है कि यह जीवन के हर पहलू के साथ कहीं न कहीं जुड़ा रहा है और कुछ हद तक इसके साथ एक समझौतावादी मानसिकता भी विकसित हो चुकी थी, किंतु जनता का जो वर्तमान आक्रोश है वह सार्वजनिक धन की खुलेआम लूट और जिन जनप्रतिनिधियों पर जनतंत्र की निगहबानी की जिम्मेदारी थी, उनकी इस लूट में या तो संलिप्तता या उसके प्रति उनकी तटस्थता से पैदा हुआ है।

सूचना क्रांति के इस युग में इंटरनेट के माध्यम से लोगों की पहुंच दूरस्थ क्षेत्रों तक बनी है और इसीलिए अन्ना हजारे के चार दिन के आमरण अनशन को देशविदेश से जैसा व्यापक समर्थन मिला, उससे फिलवक्त यह आश्वस्ति जरूर हुई है कि देश की अर्थव्यवस्था व विकास को दीमक की तरह चाट रहे भ्रष्टाचार और लूट को अब साधारण नागरिक और अधिक सहने को तैयार नहीं है, किंतु इसके लिए जिस राजनीतिक इच्छाशक्ति की जरूरत है, क्या वह भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी कांग्रेस में है? क्या लोकपाल बिल के समर्थन में खड़े अन्य राजनीतिक दलों का दामन बेदाग है? जनदबाव में यदि कांग्रेस लोकपाल बिल पारित कराने में सकारात्मक सहयोग करती है तो क्या लोकपाल बिल का मसौदा भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म कर पाने में सफल हो सकेगा?

यक्ष प्रश्न यह भी कि क्या भ्रष्टाचार को केवल एक बिल मात्र बना देने से खत्म किया जा सकता है? वस्तुतः जब तक हमारे अंदर दायित्व बोध पैदा नहीं होगा, जब तक हम अपने लिए शुचिता का मापदंड स्वतः तय नहीं करेंगे तब तक भ्रष्टाचार से मुक्ति पाने की कामना गलत है। समाज में पैदा हुई अन्य विकृतियों की तरह ही भ्रष्टाचार भी हमारी एक खास मानसिकता के कारण पैदा हुआ है। सनातन परंपराओं से हमें जो मूल्य

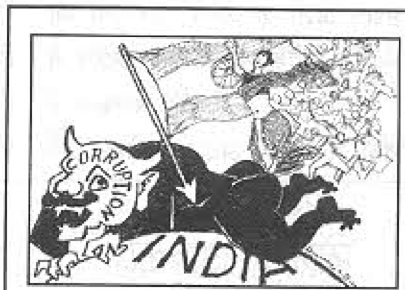

भ्रष्टाचार और लूट को अब साधारण नागरिक और अधिक सहने को तैयार नहीं है, किंतु इसके लिए जिस राजनीतिक इच्छाशक्ति की जरूरत है, क्या वह भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी कांग्रेस में है? क्या लोकपाल बिल के समर्थन में खड़े अन्य राजनीतिक दलों का दामन बेदाग है? जनदबाव में यदि कांग्रेस लोकपाल बिल पारित कराने में सकारात्मक सहयोग करती है तो क्या लोकपाल बिल का मसौदा भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म कर पाने में सफल हो सकेगा?

मिले हैं, उसके अनुरूप जब तक हम समष्टि के लिए जागृत नहीं होंगे तब तक सामाजिक बुराइयों का खात्मा भी कठिन है। समाज में आए इस पतन के लिए मैकाले–मार्क्स के मानसपुत्रों द्वारा पोषित शिक्षण व्यवस्था भी कसूरवार है, जिसने धीरे–धीरे सामाजिक मर्यादा का तानाबाना ही ध्वस्त कर डाला।

भारतीय समाज एक धर्मभीरू समाज रहा है और किसी भी गलत काम के लिए उसके अंदर अपराध भाव रहा है। वह भीरूता खत्म हुई है। समाज ने हमें जो भी दायित्व सौंपा है, उसके सकारात्मक और पारदर्शी निर्वाह के लिए स्वयं हमें ही मर्यादा की सीमाएं तय करनी होंगी। पश्चिम के भौतिकवादी दर्शन के विपरीत भारतीय जीवनपद्धति आध्यात्मिकता प्रधान रही है। हमें उन मूल्यों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है, जो लोकपाल बिल बना लेने मात्र से संभव नहीं है।

प्रधानमंत्री समेत संप्रग समन्वय समिति व कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहनशीलता बरतने का दावा कर रहे हैं, किंतु वास्तविकता इसके विपरीत है। राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन में मची लूट के लिए अब तक चार–पांच अफसरों पर ही कार्रवाई की गई है और वह भी देर से। क्या इतने बड़े पैमाने पर लूट–खसोट महज सरकारी बाबुओं की ही करतूत थी? सर्वोच्च न्यायालय की फटकार के बाद प्रधानमंत्री ने जांच के लिए शुंगलू समिति का गठन किया था। शुंगलू समिति ने कलमाड़ी के साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को भी बराबर का कसूरवार माना है। टूजी स्पेक्ट्रम घोटाले के सिलसिले में तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए राजा की गिरफ्तारी भी महज नूराकुश्ती है। गठबंधन धर्म की विवशता ने यदि प्रधानमंत्री को राजा पर कार्रवाई करने से रोक रखा था तो अब उनके हाथ क्यों बंधे हैं? जब उनकी कथनी और करनी में जमीन–आसमान का फर्क हो तो भ्रष्टाचार से लड़ने की उनकी दावेदारी पर कैसे विश्वास किया जाए? ❑

लड़ाई का अगला मोर्चा

अमेरिका को लादेन को जिंदा या मुर्दा पकड़ने में इसलिए एक दशक का समय लगा, क्योंकि उसे पाकिस्तानी रक्षा प्रतिष्ठान के कुछ तत्वों का संरक्षण हासिल था। वर्तमान अभियान को सफलता इसलिए मिली, क्योंकि पाकिस्तानी सेना और आइएसआइ से संबंध खराब होने की परवाह किए बिना अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर बड़ी संख्या में सीआईए एजेंट और स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेज को तैनात किया था। इस अभियान की भनक पाक सेना को भी नहीं लगने दी गई. . .

■ ब्रह्मा चेलानी

अमेरिकी विशेष बल के हाथों इस्लामाबाद के करीब एबटाबाद में एक शानदार बंगले में ओसामा बिन लादेन की मौत और इससे पहले अनेक अलकायदा नेताओं की पाकिस्तानी शहरों से हुई गिरफ्तारी से यह स्पष्ट हो जाता है कि आतंकवादियों की सुरक्षित पनाहगाह अफ–पाक सीमा या भारत सीमा पर नहीं, बल्कि पाकिस्तान के बीचोबीच हैं। इससे एक और मूलभूत सच्चाई रेखांकित होती है कि पाकिस्तान में सेना का वर्चस्व समाप्त किए बिना तथा वहां कट्टरपंथ को समाप्त किए बगैर अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ जंग नहीं जीती जा सकती। इसके लिए पाकिस्तान में नागरिक–सैन्य संबंधों को फिर से संतुलित करने और आइएसआइ पर लगाम कसने की सख्त जरूरत है।

9/11 हमले के बाद पाकिस्तान से पकड़े गए अन्य आतंकवादी नेताओं में अलकायदा के तीसरे नंबर का नेता शालिद शेख मोहम्मद, नेटवर्क व्यवस्था का प्रमुख अबु जुबैदिया, यासर जजीरी, अबु फरज फर्ज शामिल हैं। इन तमाम गिरफ्तारियों में एक समान कड़ी यह है कि ये सब पाकिस्तानी शहरों से पकड़े गए हैं। इस आलोक में यह हैरानी की बात नहीं है कि बिन लादेन कबीलाई इलाकों के बजाए पाकिस्तान की राजधानी के निकट शहर में मारा गया। अगर हैरानी है तो इस बात की कि ओसामा बिन लादेन इस्लामाबाद के बगल में एबटाबाद में रह रहा था। यहां पाकिस्तानी सेना का बड़ा आधार शिविर, सैन्य अकादमी, सैन्य अस्पताल और अनेक वरिष्ठ सैन्य व खुफिया अधिकारियों व पूर्व अधिकारियों के आवास हैं।

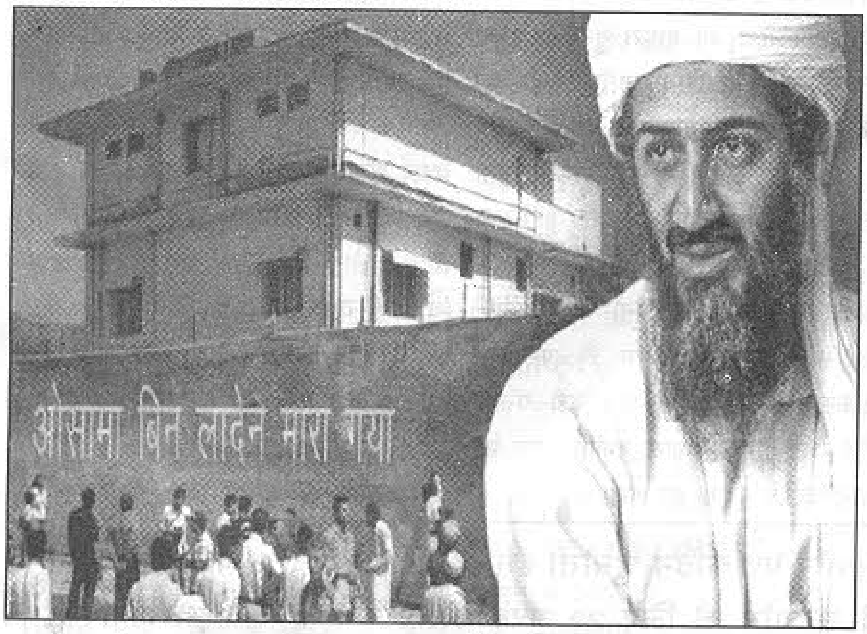

यह हैरानी की बात नहीं है कि बिन लादेन कबीलाई इलाकों के बजाए पाकिस्तान की राजधानी के निकट शहर में मारा गया। अगर हैरानी है तो इस बात की कि ओसामा बिन लादेन इस्लामाबाद के बगल में एबटाबाद में रह रहा था। यहां पाकिस्तानी सेना का बड़ा आधार शिविर, सैन्य अकादमी, सैन्य अस्पताल और अनेक वरिष्ठ सैन्य व खुफिया अधिकारियों व पूर्व अधिकारियों के आवास हैं।

इससे यह भी रेखांकित होता है कि अमेरिका को लादेन को जिंदा या मुर्दा पकड़ने में इसलिए एक दशक का समय लगा, क्योंकि उसे पाकिस्तानी रक्षा प्रतिष्ठान के कुछ तत्वों का संरक्षण हासिल था। वर्तमान अभियान को सफलता इसलिए मिली, क्योंकि पाकिस्तानी सेना और आईएसआई से संबंध खराब होने की परवाह किए बिना अमेरिका ने

वास्तव में, कभी एक देश को प्रायोजित करने वाले विश्व के सबसे बड़े आतंकी सरगना की मौत के बाद अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ युद्ध का मूल बिंदु राष्ट्र प्रायोजित आतंकवाद के खतरे का खात्मा होना चाहिए. . . हालिया वर्षों में, वरिष्ठ नेताओं की धरपकड़ और बिन लादेन के पाकिस्तान में छुपे होने से अलकायदा की बड़ा अंतरराष्ट्रीय हमला करने या फिर अमेरिका के सामने चुनौती पेश करने की क्षमता खत्म हो गई थी। बिन लादेन के मरने के बाद अलकायदा संगठन बिखरने के कगार पर पहुंच गया। फिर भी, इसकी खतरनाक विचारधारा जिंदा रहेगी और राज्य प्रायोजित गैरसरकारी तत्वों को प्रोत्साहित करती रहेगी।

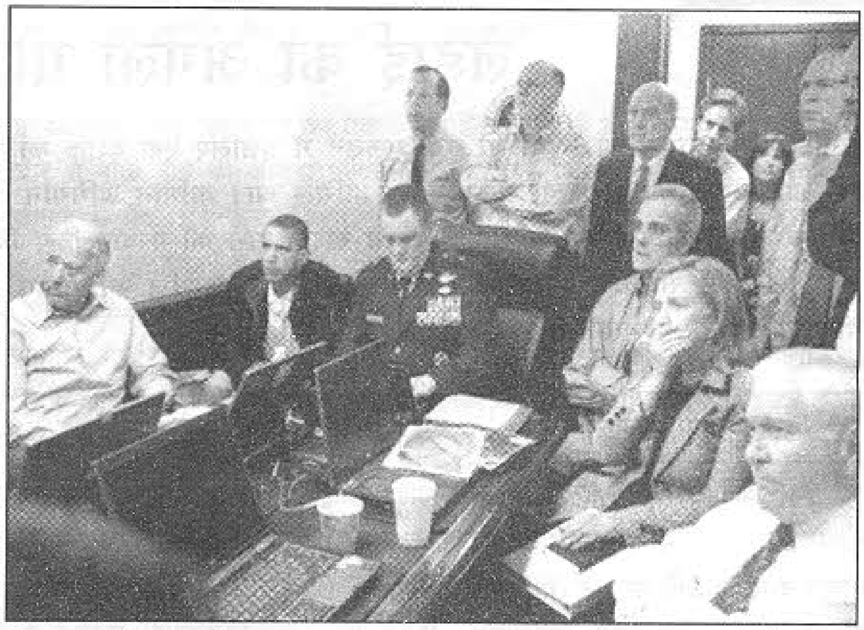

पाकिस्तान के अंदर बड़ी संख्या में सीआइए एजेंट और स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेज को तैनात किया था। इस अभियान की भनक पाक सेना को भी नहीं लगने दी गई। सीआइए एजेंट रेमंड डेविस की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान के दो सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्तियों–सैन्य प्रमुख अशफाक परवेज कयानी तथा आइएसआइ के मुखिया अहमद शुजा पाशा ने अमेरिका से मांग की थी कि वह सीआईए द्वारा पाकिस्तान में तैनात तमाम ठेकेदारों व स्पेशल फोर्सेज को वापस बुला ले तथा पाकिस्तान में खुफिया गतिविधियों पर रोक लगाए, किंतु एबटाबाद सैन्य अकादमी के बगल में आराम से रह रहे ओसामा बिन लादेन के खिलाफ सफल अभियान के बाद अब पाकिस्तान के मुख्य भागों में स्वतंत्र खुफिया ऑपरेशनों की जरूरत बढ़ गई है। लंबे समय से अमेरिका पाकिस्तानी जिहादियों के किले पंजाब और कराची के बजाय वजीरिस्तान पर ध्यान केंद्रित किए हुए था।

वास्तव में, कभी एक देश को प्रायोजित करने वाले विश्व के सबसे बड़े आतंकी सरगना की मौत के बाद अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ युद्ध का मूल बिंदु राष्ट्र प्रायोजित आतंकवाद के खतरे का खात्मा होना चाहिए। बिन लादेन की मौत के बाद अलकायदा में अल जवाहिरी के अलावा कोई अन्य बड़ा आतंकी नहीं बचा है, किंतु वह आतंकी तंत्र चलाने में समर्थ नहीं है। हालिया वर्षों में, वरिष्ठ नेताओं की धरपकड़ और बिन लादेन के पाकिस्तान में छुपे होने से अलकायदा की बड़ा अंतरराष्ट्रीय हमला करने या फिर अमेरिका के सामने चुनौती पेश करने की क्षमता खत्म हो गई थी।

अमेरिका के लिए पाकिस्तान खासतौर पर कठिन चुनौती है। 9/11 के बाद से पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सहयोग के लिए 20 अरब डॉलर देने के बावजूद अमेरिका को बदले में छद्म सहयोग और धोखा ही मिला है। आज, अमेरिकावाद के खिलाफ उठे ज्वार और कयानी व पाशा की मांगों के बाद अमेरिका की पाक नीति की विफलता जाहिर हो जाती है। बिन लादेन की मौत पर आज अमेरिकी जश्न जरूर मना रहे हैं, लेकिन वाशिंगटन को इस पर विचार करना चाहिए कि उसकी विफल पाक नीति का ही नतीजा है कि आज पाकिस्तान आतंकवादियों की शरणस्थली बन चुका है।

पाकिस्तानी सेना और आईएसआई में सुधार के बिना आतंकवाद को खत्म नहीं किया जा सकता और न ही इसके बिना पाकिस्तान में राष्ट्र निर्माण संभव है। जब तक सत्ता पर सेना की पकड़ बनी रहेगी तब तक पाकिस्तान विश्व के लिए आतंकी चुनौती बना रहेगा।

बिन लादेन के मरने के बाद अलकायदा संगठन बिखरने के कगार पर पहुंच गया। फिर भी, इसकी खतरनाक विचारधारा जिंदा रहेगी और राज्य प्रायोजित गैरसरकारी तत्वों को प्रोत्साहित करती रहेगी।

ये ऐसे तत्व हैं जो 26/11 जैसे बड़े हमले करने की क्षमता रखते हैं। यहां तक कि अफगानिस्तान में भी अमेरिका का बड़ा दुश्मन अलकायदा नहीं, तालिबान है, जिसे पाकिस्तान में सुरक्षित पनाह मिलती है। लादेन की मौत के बाद अब पाकिस्तान में आतंकी परिसर और सरकार व गैरसरकारी तत्वों के संबंध निशाने पर होंगे। महत्वपूर्ण है कि जैसे ही सीआइए बिन लादेन के करीब पहुंची, यूएस ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष ने पहली बार सार्वजनिक रूप से कहा कि पाकिस्तानी सेना और अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना पर हमले करने वालों के बीच निकट संबंध हैं।

अमेरिका के लिए पाकिस्तान खासतौर पर कठिन चुनौती है। 9/11 के बाद से पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सहयोग के लिए 20 अरब डॉलर देने के बावजूद अमेरिका को बदले में छद्म सहयोग और धोखा ही मिला है। आज, अमेरिकावाद के खिलाफ उठे ज्वार और कयानी व पाशा की मांगों के बाद अमेरिका की पाक नीति की विफलता जाहिर हो जाती है। बिन लादेन की मौत पर आज अमेरिकी जश्न जरूर मना रहे हैं, लेकिन वाशिंगटन को इस पर विचार करना चाहिए कि उसकी विफल पाक नीति का ही नतीजा है कि आज पाकिस्तान आतंकवादियों की शरणस्थली बन चुका है। पाकिस्तान में नागरिक संस्थानों को मजबूती प्रदान करने के बजाए वाशिंगटन जिहादियों में पैठ रखने वाले पाक सैन्य प्रतिष्ठान को मजबूत करने में लगा रहा।

तानाशाह परवेज मुशर्रफ की बेदखली के बाद नई नागरिक सरकार ने आईएसआई को गृह मंत्रालय के अधीन करने के आदेश जारी किए थे, लेकिन उसे अमेरिका से समर्थन नहीं मिला और पाक सेना ने इस आदेश को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद ओबामा ने अफगानिस्तान में सैन्य बल में बढ़ोतरी करने के साथ-साथ पाक की आर्थिक सहायता में भी वृद्धि की।

इससे अमेरिका गलत युद्ध में उलझ गया, क्योंकि इस राशि के एक हिस्से से पाकिस्तान अफगान तालिबान को पोषित करने में लगा रहा। पाकिस्तान में आतंकवाद के प्रसार में मुल्लाओं से अधिक स्कॉच पीने वाले सैन्य अफसरों का हाथ है, लेकिन उन्होंने बड़ी चतुराई से इसका दोष मुल्लाओं के सिर मढ़ दिया और अमेरिका की निगाह में पाक-साफ बने रहे।

पाकिस्तानी सेना और आईएसआई में सुधार के बिना आतंकवाद को खत्म नहीं किया जा सकता और न ही इसके बिना पाकिस्तान में राष्ट्र निर्माण संभव है। जब तक सत्ता पर सेना की पकड़ बनी रहेगी तब तक पाकिस्तान विश्व के लिए आतंकी चुनौती बना रहेगा। अलकायदा के पुनरुत्थान की एकमात्र सूरत यह है कि 2014 के बाद पाक सेना अफगानिस्तान में छद्म सरकार का गठन करने में कामयाब हो जाए। ❑

आज भी नहीं मिल पाया है श्रमिकों को सम्मान

यह सच है कि एक मई को पूंजीवाद ने घुटने टेके। इस आधार पर यह दिवस श्रम सम्मान का दिन है। किन्तु उससे भी अधिक भयावह सच यह है कि एक मई को श्रम शोषण की पहली ईट रखी गई . . . .किन्तु एक मई के बाद बुद्धिजीवियों ने ऐसा कमाल किया कि श्रम शोषण बढता गया और दिखना बन्द हो गया। गांधी जी ने स्पष्ट कहां था कि श्रम सम्मान और श्रम मूल्य बढ़ना चाहिये। मशीनों का उपयोग अनिवार्य स्थिति में किया जाय जब या तो श्रम अभाव हो जाय या श्रम संभव कार्य न हो। बुद्धिजीवियों ने गांधी की बात को किनारे करकें मार्क्स को बीच मे घुसा दिया कि मशीनों का अधिकाधिक उपयोग करके उसका लाभ श्रमजीवियों में बांट दिया जाए।

■ बजरंग मुनि

फिर एक मई आया और चला गया। प्रतिवर्ष आता है और चला जाता है। नारे लगतें हैं जुलूस निकलते है और कुछ श्रमजीवियों को सम्मानित भी कर दिया जाता है। साथ ही आयोजकों को मिल जाता है अपनी श्रम शोषक नीतियों को एक वर्ष तक जारी रखने का अधिकार । जिस देश में कई दशकों से एक मई श्रम दिवस के रूप मे मनाया जाता हो और उस देश का श्रम जीवी आज भी नरेगा के अंतर्गत एक सौ बीस रूपया प्रतिदिन पर काम करने के लिये सड़को पर भीख का कटोरा लिये घूम रहा हो वहां श्रम दिवस की उपयोगिता पर खोजबीन तो होनी ही चाहिये।

प्राचीन समय में पूंजीवाद था। पूंजीवाद प्रायः श्रम शोषण के लिये लालायित रहता है। बुद्धिजीवी वर्ग पूजीवाद से श्रम की सुरक्षा के प्रयत्न करता रहता है। न सभी पूंजीपति बुरे होते है न सभी बुद्धिजीवी अच्छे। बुरा और अच्छा होना व्यक्ति की व्यक्तिगत सोच पर निर्भर करता है। यह प्रश्न विशेष अर्थ नही रखता कि वह व्यक्ति पूंजीपति है, बुद्धिजीवी अथवा श्रमजीवी। किन्तु यह बात तब ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है जब ऐसे चालाक लोगो का सत्ता के साथ गठजोड हो जाता है। पूंजी ने श्रम को तो गुलाम बनाया ही, बुद्धिजीवीयों को भी साथ कर लिया। बुद्धिजीवियो ने इस पूंजीवादी अत्याचार के विरूद्ध रिवोल्ट किया। उन्होने साम्यवाद समाजवाद के नाम पर श्रम जीवियों को आगे कर दिया। पूंजीवाद ने कई जगह घुटने टेक दिये। यह घुटने टेकने की घटना एक मई को हुई थी। इसलिये इस घटना की यादगार के रूप मे एक मई को मजदूर दिवस के रूप मे मनाया जाता है।

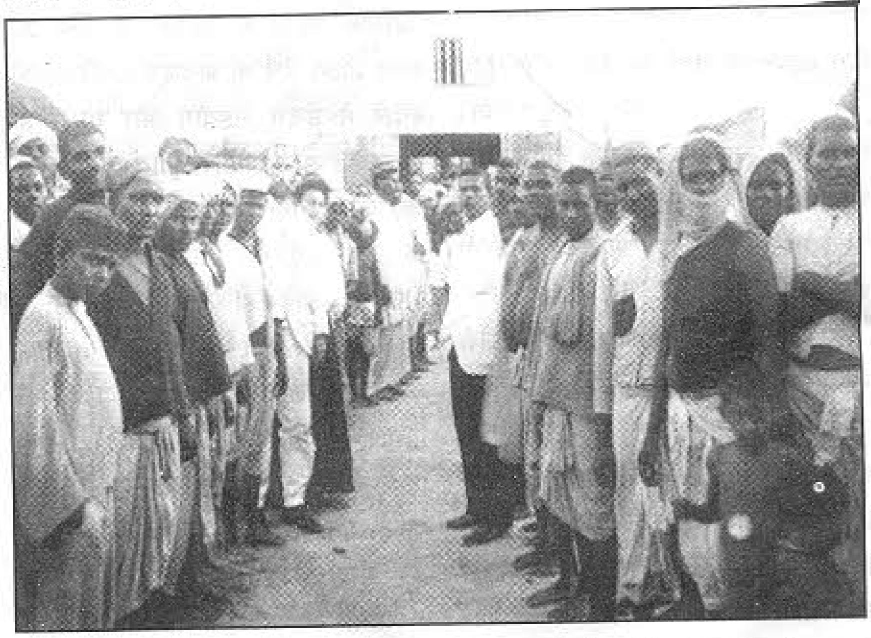

यह सच है कि एक मई को पूंजीवाद ने घुटने टेके। इस आधार पर यह दिवस श्रम सम्मान का दिन है। किन्तु उससे भी अधिक भयावह सच यह है कि एक मई को श्रम शोषण की पहली ईट रखी गई। अब तक पूंजीवाद प्रत्यक्ष रूप से श्रम शोषण करता भी था और दिखता भी था। किन्तु एक मई के बाद बुद्धिजीवियों ने ऐसा कमाल किया कि श्रम शोषण बढता गया और दिखना बन्द हो गया। गांधी जी ने स्पष्ट कहा था कि श्रम सम्मान और श्रम मूल्य बढ़ना चाहिये। मशीनों का उपयोग अनिवार्य स्थिति में किया जाय जब या तो श्रम अभाव हो जाय या श्रम संभव कार्य न हो। बुद्धिजीवियों ने गांधी की बात को किनारे करकें मार्क्स को बीच मे घुसा दिया कि मशीनों का अधिकाधिक उपयोग करके उसका लाभ श्रमजीवियों में बांट दिया

जाए।

सबसे बडा घपला यह हुआ कि बुद्धिजीवियो ने श्रम की स्वाभाविक परिभाषा 'शारीरिक श्रम'' को बदल कर उसके साथ बौद्धिक श्रम को जोड लिया। इस परिवर्तन से बुद्धिजीवियों का रास्ता साफ हो गया। ये लोग श्रमजीवियों के नाम पर नीतियां बनाने लगे, संगठन बनाने लगे, सरकार बनाने लगे और उससे भी ज्यादा शक्तिशाली हो बैठे जहां पहले पूंजीपति हुआ करते थे। इन लोगों ने सबसे पहले शिक्षा को महत्व दिलाना शुरू किया। ये श्रम को धक्का देकर शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान देने में पूरी तरह सफल है। आज भी श्रम का बजट काटकर शिक्षा का बजट बढाने की षड़यंत्रकारी आवाजें उठती ही रहती है और बुद्धिजीवियों की सरकार ऐसी मांग तुरंत मान भी लेती है। शिक्षा पर बजट बढाना गलत नही है। श्रम को उचित मूल्य और सम्मान मिलने लगे और शेष बजट शिक्षा पर खर्च हो यह ठीक हैं। किन्तु शिक्षा पर बजट बढ़े चाहे उसके लिये रोटी, कपडा, मकान, दवा जैसी मूलभूत आवश्यकताओं पर ही टैक्स क्यों न लगाना पडे यह गलत है। साठ वर्षों के बाद भी एक सौ बीस रूपये में श्रम को वर्ष भर काम देने के लिये हमारे पास पर्याप्त धन नही है। दूसरी ओर शिक्षा पर अनाप सनाप बजट खर्च होता है तो

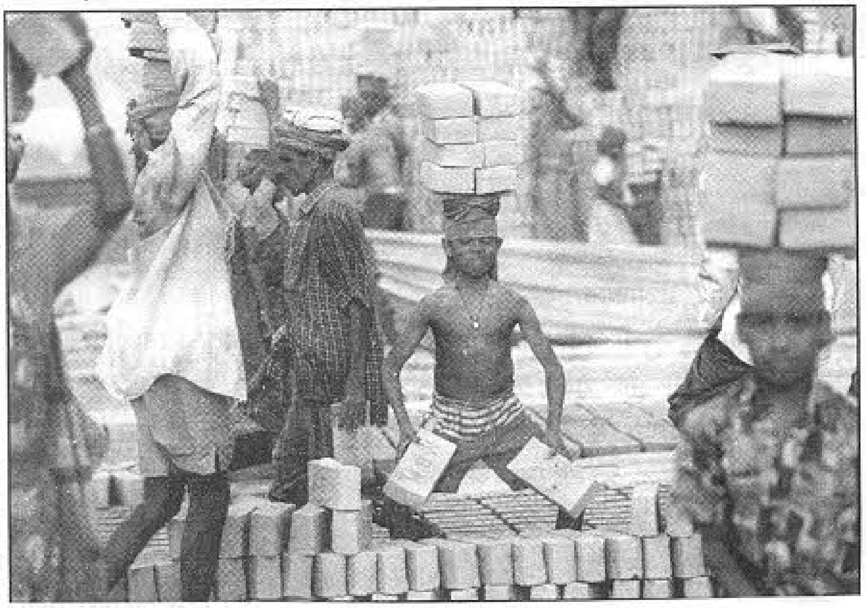

सबसे बडा घपला यह हुआ कि बुद्धिजीवियो ने श्रम की स्वाभाविक परिभाषा 'शारीरिक श्रम'' को बदल कर उसके साथ बौद्धिक श्रम को जोड़ लिया। इस परिवर्तन से बुद्धिजीवियों का रास्ता साफ हो गया। ये लोग श्रमजीवियों के नाम पर नीतियां बनाने लगे, संगठन बनाने लगे, सरकार बनाने लगे और उससे भी ज्यादा शक्तिशाली हो बैठे जहां पहले पूंजीपति हुआ करते थे।

बुद्धिजीवियो की नीयत पर संदेह तो होता ही है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ग्रामीण उत्पादन और उपभोग की वस्तुओं पर इतना ज्यादा कर है। किन्तु है तो। मेरे बार बार प्रश्न करते रहने के बाद भी किसी बुद्धिजीवी मे हिम्मत नहीं हुई कि वे इस प्रश्न पर कुछ कहे।

श्रम शोषकों का मनोबल बढ़ा। इन लोगों ने नई चालाकी करते हुए कृत्रिम उर्जा को अधिकाधिक सस्ता करने रहने की योजना बना ली। एक तीर से कई शिकार हो गये। श्रम मूल्य को बढने से रोकने में यह प्रयत्न बहुत कारगर रहा। क्योकि यदि कृत्रिम उर्जा की मूल्य वृद्धि हो जाती तो वे सारी समस्याएं स्वतः ही दूर हो जाती जिनके आधार पर श्रमिको के बीच असंतोष की ज्वाला जलाकर रखी जा सकती थी। इस माध्यम से आर्थिक असमानता बढती गई, गांव कमजोर और शहर मजबूत होने लगे। खेती को श्रम के साथ जोड़ दिया गया जबकि बुद्धि को उद्योग या सरकारी नौकरी के साथ। नौकरी और उधोग को लाभ कर और खेती को लगातार अलाभकार धंधा बनाने की कोशिश की गई। खेती के उत्पादन के मूल्यो को बढने से रोका

आज भी श्रम का बजट काटकर शिक्षा का बजट बढाने की षड़यंत्रकारी आवाजें उठती ही रहती है और बुद्धिजीवियों की सरकार ऐसी मांग तुरंत मान भी लेती है। शिक्षा पर बजट बढाना गलत नही है। श्रम को उचित मूल्य और सम्मान मिलने लगे और शेष बजट शिक्षा पर खर्च हो यह ठीक हैं। किन्तु शिक्षा पर बजट बढ़े चाहे उसके लिये रोटी, कपडा, मकान, दवा जैसी मूलभूत आवश्यकताओं पर ही टैक्स क्यों न लगाना पड़े यह गलत है।

गया। लगातार मंहगाई का झूठा हल्ला इस प्रकार जीवित रखा गया कि खेती से जुडे उत्पादनो का मूल्य बढ ही न सके। खेती से जुडे उत्पादनों पर कई प्रकार के टैक्स और कानून लाद दिये गये। साइकिल पर चार सौ रूपया प्रति साइकिल टैक्स और दूसरी ओर टेलीफोन, कम्प्यूटर, आवागमन आदि उच्च तकनीक को अधिकाधिक उपयोगी और सरता बनाया गया जो बौद्धिक जगत के उपयोग में ज्यादा आती है। एक श्रमिक को सौ रूपये प्रतिदिन में भी काम नही मिलता।

इसके बाद भी सम्पूर्ण भारत मे लगातार यह प्रचारित किया जा रहा है कि आज भारत में काम करने को मजदूर नही मिलते। आश्चर्य है कि आपको एक पद की आवश्यकता होने पर कई हजार आवेदन प्राप्त होते है दूसरी ओर खोजने पर भी मजदूर नहीं मिलते। क्योकि उस एक पद के लिये आवेदन के साथ है अच्छा वेतन, अच्छी घूस, सुविधा और सम्मान जनक कार्य और ऊपर से पद का रोब। श्रमिक कार्य में क्या जुडा है? एक सौ रूपया, मालिक –नौकर के संबंध, ऊपर से डांट डपट। विचार करिये कि आज मई दिवस ने शारीरिक श्रम का क्या हाल कर रखा है?

इन सब असमानताओ के बाद भी हालत यह है कि यदि मजदूर नहीं मिलते तो नरेगा में एक सौ बीस रूपया में मजदूर कहां से मिल रहे हैं कि आपको एक सौ दिन की सीमा घोषित करनी पडी। यदि आप एक सौ बीस रूपया मे भी खुला काम नही दे पा रहे तो भारत मे काम करने वालों का अभाव सिद्ध होता है कि काम देने वालो का अभाव। स्पष्ट है कि गांवो में श्रमिक है और शहरों मे श्रमिको की मांग है। नरेगा में भी मशीनों का प्रयोग होने लगा है क्योकि डीजल, पेट्रोल, बिजली का उपयोग सस्ता भी है और सुविधाजनक भी। मजदूर मशीन की अपेक्षा महंगा है। पूरे भारत मे गरीब ग्रामीण श्रमजीवी के शोषण के उद्देश्य से शहरी पूंजीपति बुद्धिजीवी वर्ग तरह तरह के षड़यंत्र कर रहा है। और उस षड़यंत्र मे सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है सस्ती कृत्रिम ऊर्जा। कृत्रिम ऊर्जा को इतने आकर्षक तरीके से गांव गांव तक पहुचाया जा रहा है कि बेचारा श्रमजीवी उसकी चकाचौंध में यह समझ ही नही पाता कि यह तो उसकी सौत है प्रतिस्पर्धी है, उसे बेरोजगार कर देगी।

मई दिवस बौद्धिक श्रम करने वालों के लिये वरदान है। उन्हे पूंजीपतियों के समानांतर एक पहचान मिली है। उन्हे शारीरिक श्रम करने वालों का शोषण करने का अधिकार मिला है। उन्हे राज्य सत्ता मे भागीदारी मिली है तथा उनकी प्रगति के द्वार खुले है । दूसरी ओर एक मई शारीरिक श्रम करने वालों के लिये एक कलंक का दिन है। यही वह दिन है जब श्रम के नाम पर संगठित बुद्धिजीवी समाज से और अधिक वेतन भत्ते सुविधाएं बजट आदि की मांग करते हैं और पा भी जाते है । दूसरी ओर श्रम मूल्य को मुद्रा स्फीति के साथ भी जोडने मे कठिनाई हो रही है। भारत की कुल विकास दर नौ प्रतिशत करीब है। यह पूंजीपतियों की सत्रह बुद्धिजीवियों की नौ तथा श्रमजीवियों की एक प्रतिशत का औसत है। यह एक प्रतिशत की विकास दर भी सरकार द्वारा प्राप्त सस्ते

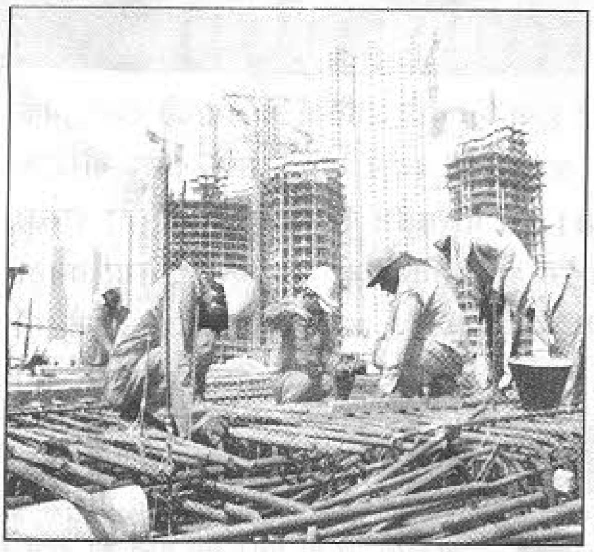

मई दिवस बौद्धिक श्रम करने वालों के लिये वरदान है। उन्हे पूंजीपतियों के समानांतर एक पहचान मिली है। उन्हे शारीरिक श्रम करने वालों का शोषण करने का अधिकार मिला है। उन्हे राज्य सत्ता मे भागीदारी मिली है तथा उनकी प्रगति के द्वार खुले है । दूसरी ओर एक मई शारीरिक श्रम करने वालों के लिये एक कलंक का दिन है। यही वह दिन है जब श्रम के नाम पर संगठित बुद्धिजीवी समाज से और अधिक वेतन भत्ते सुविधाएं बजट आदि की मांग करते हैं और पा भी जाते है। दूसरी ओर श्रम मूल्य को मुद्रा स्फीति के साथ भी जोड़ने मे कठिनाई हो रही है।

अनाज, नरेगा द्वारा प्राप्त रोजगार तथा अन्य सुविधाओं के कारण है अन्यथा विकास दर नकारात्मक ही है।

साम्यवाद ने सम्पूर्ण भारत मे श्रम को धोखा देकर उनकी स्वाभाविक विकास दर को रोकने की पहल की है। कृत्रिम ऊर्जा की मूल्य वृद्धि के खिलाफ सबसे आगे साम्यवादी ही खडे होते है क्योंकि उन्हे डर है कि यदि कृत्रिम ऊर्जा की भारी मूल्य वृद्धि होगी तो श्रम की स्वाभाविक मांग बढ़ जाएगी और इससे गरीब ग्रामीण श्रमजीवी के अंदर निरंतर जलायी जा रही असंतोष की ज्वाला बुझ सकती हैं जो ज्वाला साम्यवाद का एक मात्र आधार है। अब नये परिप्रेक्ष्य मे एक मई को श्रम शोषण दिवस के रूप मे मनाने की पहल करनी चाहिये क्योकि एक मई ने मजदूरों को सशक्त किया है, उन्हे आजादी दिलाई है किन्तु श्रम को उससे दूर रखने का षड़यंत्र भी किया है। अब तक श्रम ऐसे झूठे प्रचार से बहुत छला गया। अब नही छला जाएगा।

साम्यवाद का पतन निश्चित हो चुका है, कृत्रिम ऊर्जा की मूल्य वद्धि के भी प्रयास शुरू हो चुके है, श्रम के नाम पर संगठित बुद्धिजीवी ब्लैकमेलिंग चुपचाप दम तोड रही है। श्रम के नाम पर धोखा देकर श्रम शोषण करने वाले महत्वहीन हो रहे है। किन्तु इन सबके बाद भी शारीरिक श्रम मजबूत न होकर पूंजीवाद ही दुबारा आ रहा है जो अच्छे आसार नही है। यदि साम्यवाद का स्थान पूंजीवाद ने ले भी लिया तो भले ही भ्रष्टाचार घट जावे, आर्थिक विकास दर बढ जावे, दुनिया मे भारत एक नम्बर हो जावे किन्तु बेचारा श्रम तो इससे कोई लाभ नहीं उठा सकेगा क्योकि श्रम को लाभ होगा कृत्रिम ऊर्जा की भारी मूल्य वृद्धि से, कृषि को लाभकारी व्यवसाय के रूप मे स्थापित होने से ग्राम सभाओ के वास्तविक सशक्तिकरण से। पूंजीवाद अब तक इन दिशाओं मे उदासीन है। शारीरिक श्रम को बौद्धिक श्रम के षडयंत्र से मुक्त होना ही पर्याप्त नही है, पर्याप्त होगा श्रम की मांग का बढना, उसका महत्व बढ़ना। हमे भारत के प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह जी से बहुत आशाएं है। जिस तरह उन्होने संसदीय लोकतंत्र को सहभागी लोकतंत्र की दिशा देने की पहल की है उसी तरह वे श्रम के साथ भी न्याय करने की पहल करें।

हमें अन्तिम रूप से यह स्वीकार करना चाहिये कि श्रम, बुद्धि और धन के बीच समानता न तो संभव है न उचित। साथ ही हमे यह भी मानना होगा कि इनके बीच बढ़ती अनियंत्रित असीमित असमानता समाज मे कभी शान्ति पैदा नहीं होने देगी। मार्क्सवाद ने समानता का असंभव लालीपाप दिखाकर इतने वर्षो तक श्रम को छला। अब पूंजीवाद श्रम को दबाना शुरू करेगा। हम जितनी जल्दी वास्तविकता को समझकर श्रम बुद्धि और धन के बीच असमानता की एक संभव रेखा खींच ले और उस रेखा के आधार पर असमानता दूर करने का प्रयास करें तो संभव है कि समाज मे वास्तविक शान्ति दिखनी शुरू हो। ❑

आश्चर्य है कि आपको एक पद की आवश्यकता होने पर कई हजार आवेदन प्राप्त होते है दूसरी ओर खोजने पर भी मजदूर नहीं मिलते। क्योंकि उस एक पद के लिये आवेदन के साथ है अच्छा वेतन, अच्छी घूस, सुविधा और सम्मान जनक कार्य और ऊपर से पद का रोब। श्रमिक कार्य में क्या जुड़ा है? एक सौ रूपया, मालिक –नौकर के संबंध, ऊपर से डांट–डपट। विचार करिये कि आज मई दिवस ने शारीरिक श्रम का क्या हाल कर रखा है?

आम आदमी पर कर का बोझ

दूसरी ओर क्रिकेट और कारपोरेट को दी जाती है भारी कर रियायतें

क्रिकेट को खुराक मिलती है, 'कारपोरेट पॉवर' से और बदले में 'क्रिकेट गेम' साम्राज्य विस्तार करता है, 'कारपोरेट पॉवर' का। यही कारण है कि क्रिकेट में सबकुछ कारपोरेट तर्ज पर ही चलता है, क्योंकि वहाँ खेल के मैदान से लेकर अंतःपुर तक सब जगह कारपोरेट कठपुतलियां ही उछल-कूद कर रही हैं। दर्शकगण क्रिकेट के जुनून या नशे से कुछ इस तरह बँधे रहते हैं कि खेल में पल-प्रतिपल घटित होने वाले उतार-चढ़ाव, आने वाले नाजुक निर्णायक मोड़. . .

■ डॉ. कृष्णस्वरूप आनन्दी

क्रिकेट-कारपोरेट गठबंधन

क्रिकेट और कारपोरेट,दोनों एक दूसरे से अभिन्न रूप में जुड़े हैं। क्रिकेट खेलों के प्रयोजन, क्रिकेटरों की नीलामी, 'ब्रांड एम्बेसडरों' के रूप में क्रिकेटरों का इस्तेमाल, सबसे बड़ी 'मनी गेम' के रूप में क्रिकेट का अवतरण, क्रिकेट में बेतहाशा बढ़ते निवेश – इन सबके पीछे बड़े-बड़े ताकतवर कारपोरेट समूह, धनकुबेर, सटोरिये तथा उनके रहमोकरम पर जीने वाले शिखण्डी राजनेता हुआ करते हैं। 'कारपोरेट पॉवर' के एक कौतुक के रूप में तेजी से उभरा है 'क्रिकेट गेम'। क्रिकेट को खुराक मिलती है, 'कारपोरेट पॉवर' से और बदले में 'क्रिकेट गेम' साम्राज्य विस्तार करता है, 'कारपोरेट पॉवर' का। यही कारण है कि क्रिकेट में सबकुछ कारपोरेट तर्ज पर ही चलता है, क्योंकि वहाँ खेल के मैदान से लेकर अंतःपुर तक सब जगह कारपोरेट कठपुतलियां ही उछल-कूद कर रही हैं। दर्शकगण क्रिकेट के जुनून या नशे से कुछ इस तरह बँधे रहते हैं कि खेल में पल-प्रतिपल घटित होने वाले उतार-चढ़ाव, आने वाले नाजुक निर्णायक मोड़ और अंततोगत्वा जय-पराजय के चलते वे मनोवैज्ञानिक रूप से इतने ज्यादा तनाव दबाव में आ जाते हैं कि कभी-कभी उनमें से कईयों की तो हृदयगति तक रूक जाती है।

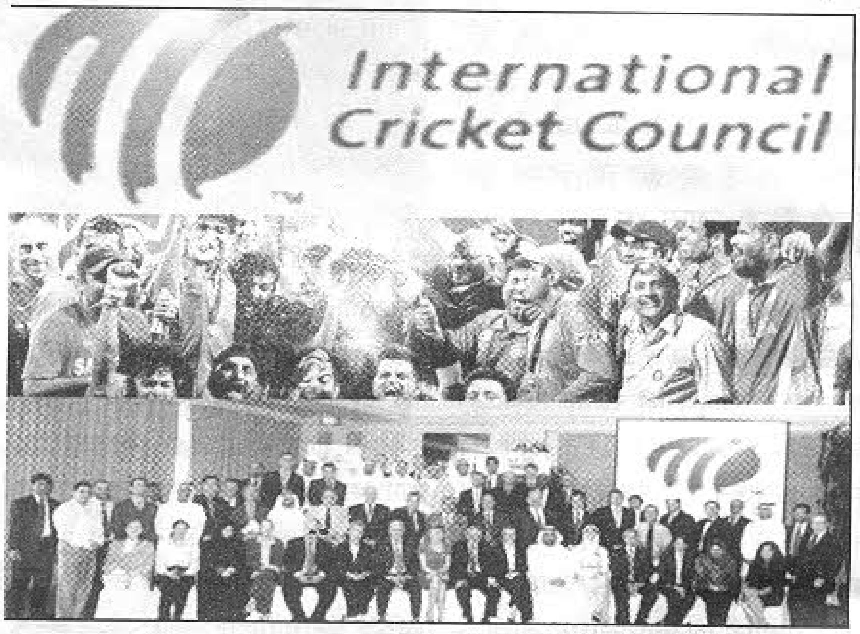

लंदन में आईसीसी का जन्म हुआ था। इस 'मनी गेम' ने एक बहुत बड़े कारोबार का रूप ले लिया। अकूत धनवर्षा होने लगी। कहने का मतलब यह है कि धनागम दिन दूना रात चौगुना बढ़ता। अपने कारोबारी साम्राज्य विस्तार की दृष्टि से आईसीसी ने एक कारपोरेट सब्सिडियरी का गठन किया।

आईसीसी के विश्वकप के कर-मुक्त दर्जा

आईसीसी (अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद्) का विश्व कप एक बहुत बड़े कारपोरेट कारोबार का रूप ले चुका है। ताजा घटनाक्रम में भारत सरकार ने उसे कर-मुक्त बिजनेस का दर्जा दिया है यानी आईसीसी को इस आयोजन के निमित्त 45 करोड़ की अच्छी खासी कर रियायत का तोहफा मिला है। मौजूदा विश्व कप में आईसीसी को राजस्व प्राप्ति 1,476 करोड़ रुपयों की है जबकि व्यय 571 करोड़ रुपयों का और ऊपर से वह कर-मुक्त घोषित यानी बीसों उंगुलियां घी में थी।

लंदन में आईसीसी का जन्म हुआ था। इस 'मनी गेम' ने एक बहुत बड़े कारोबार का रूप ले लिया। अकूत धनवर्षा होने लगी। कहने का मतलब यह है कि धनागम दिन दूना रात चौगुना बढ़ता। अपने कारोबारी साम्राज्य विस्तार की दृष्टि से आईसीसी ने एक कारपोरेट सब्सिडियरी का गठन किया और कर–पनाहगाह मोनाको में उसका कार्यालय खोला गया। लंदन से मोनाको और मोनाको से लंदन की आवाजाही के चलते आईसीसी को घोर असुविधा होने लगी। इसीलिए उसने इंग्लैंड की सरकार के समक्ष यह प्रस्ताव रखा कि अगर उसके बिजनेस को कर–मुक्त दर्जा दिया जाए, तो वह मोनाको से सब्सिडियरी को समेटकर उसे लंदन में स्थानांतरित करना चाहेगी। जब सरकार से मनाही हो गयी, तब उसने दुबई की ओर रुख किया।

कारपोरेट सेक्टर को मिलने वाली राहतें भारत सरकार के बजट को गड़बड़ाती हैं।

कारपोरेट सेक्टर भारत सरकार से मजे लूटने वालों में अग्रणी है। भारत में सबसे ज्यादा सब्सिडी, छूट या राहत अगर कोई वर्ग केन्द्रीय बजट के जरिए पा रहा है तो वह वर्ग कारपोरेट घरानों का है। आयकर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, निर्यात प्रोत्साहन आदि विभिन्न मदों में जो भारी छूट इस वर्ग को वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान मिलने जा रही है, वह राशि लगभग 6 लाख करोड़ रुपयों की होगी। वर्ष 2005–06 से लेकर वर्ष 2010–11 तक आयकर, उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क के मदों में इस वर्ग को दी गयी रियायतों के चलते भारत सरकार ने 21,25,023 करोड़ रुपए गँवाए। कारपोरेट घरानों को दी जा रही बड़ी–बड़ी राहतों के चलते भारत सरकार को होने वाली राजस्व–प्राप्तियों में भरी छेद हो जाता है। भारत सरकार का बजट बुरी तरह गड़बड़ा जाता है, राजकोषीय घाटा बढ़ता जाता है और इनके फलस्वरूप सरकार की निर्भरता देशी–विदेशी स्रेतों से उधारी, सार्वजनिक उपक्रमों की बिक्री और बेश कीमती दुर्लभ संसाधनों की नीलामी पर जा टिकती है। 'दि हिन्दू (दिल्ली संस्करण) में 7 मार्च 2011 को छपे पी साईनाथ के लेख 'कारपोरेट सोशलिज़्म 2 जी ऑर्जी' में जो तालिका दी गयी है। वह वर्ष 2005–06 से लेकर 2010–11 तक कारपोरेट घरानों को आयकर, उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क के मदों में दी गयी राहतों का खुलासा करती हैं। (देखें तालिका')

भारत सरकार द्वारा कॉरपोरेट सेक्टर को दी गयी कर–रियायतें (करोड़ रूपये में)

मद	वित्तीय वर्ष					
	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11
आयकर	34,618	50,075	62,199	66,9017	2,881	88,263
उत्पाद शुल्क	66,760	99,690	87,468	1,28,293	1,69,121	1,98,291
सीमा शुल्क	1,27,730	1,23,682	1,53,593	2,25,752	1,95,288	1,74,418
योगफल	2,29,108	2,73,447	3,03,260	4,20,946	4,37,290	4,60,972

कॉरपोरेट घराने न केवल अपने कारोबार के जरिए देश को खोखला बना रहे हैं, बल्कि कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका को मोहरा बनाकर बड़े–बड़े घोटालों या खतरनाक कारनामों से देश की सम्पदा बेहिसाब लूट रहे हैं। लेकिन बजट में उन्हें जो भारी छूट दी जा रही है, वह खुल्लमखुल्ला एक बहुत बड़ी डकैती है।

पी. साईनाथ ने हिसाब लगाया है कि वर्ष 2005–06 से लेकर वर्ष 2010–11 तक कॉरपोरेट सेक्टर को केन्द्रीय बजटों के माध्यम से जो राहतें दी गयी हैं, वे 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन में हुए घोटाले की रकम से 12 गुनी ज्यादा है। 'ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी' का मानना है कि विदेशों में 1948 से लेकर अब तक भारत से जमा हो चुके कालेधन की रकम 462 अरब डॉलर है। ध्यान देने की बात है कि पिछले 6 वर्षों के दौरान केन्द्रीय बजटों के माध्यम से आयकर, उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क के मदों में कॉरपोरेट सेक्टर को कुल 21,25,023 करोड़ रुपए की राहतें दी जा चुकी हैं। ये दोनों रकमें लगभग बराबर हैं।

क्रिकेट की नाभि रज्जु

क्रिकेट की नाभि रज्जु जब तक कॉरपोरेट सत्ता से जुड़ी रहेगी, तब तक वह खेल नहीं रहेगा। वह दरअसल रहेगा ऐसा 'मनीगेम' जिसका इस्तेमाल बहुराष्ट्रीय औपनिवेशक तंत्र के संजाल को बढ़ाने के लिए होता रहेगा। ऐसी प्रतीत देश के जनगण को कब होगी कि क्रिकेट हमारी राष्ट्रीय संप्रभुता या सांस्कृतिक अस्मिता का प्रतीक नहीं, बल्कि बहुराष्ट्रीय कॉरपोरेट उपनिवेशवाद का जबरदस्त, ताकतवर और खतरनाक वाहक है वह। हमें क्रिकेट के उन्माद से बचना होगा और क्रिकेट को कॉरपोरेट जगत का मोहर बनाने से रोकना होगा। ❑

सामाजिक मूल्यों का पतन और स्वदेशी

स्वदेशी जागरण मंच विगत 20 वर्षों में सिर्फ स्वदेशी वस्तुओं और स्वदेशी अर्थव्यवस्था की बात नहीं करता। बल्कि विदेशी या चीनी सामान, मॉल संस्कृति का इत्यादि का विरोध इसलिए करता है क्योंकि ये सभी हमारी भारतीय संस्कृति और अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। हमारे लिए ग्राम को पूर्व इकाई बनाने की सोच है। हम मॉल संस्कृति को इसलिए विरोध करते हैं क्योंकि यह हमारे खुदरा व्यापार को समाप्त कर देगा।

■ विश्वतोष श्रीवास्तव

आज समाज का विकृत रूप अपनी पराकाष्ठा पर है, पूरे देश में भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है। हर दिन उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम चारों दिशाओं से भ्रष्टाचार और दुराचार, अनाचार की ही खबरें सुनने को मिल रही है। पूरा राष्ट्र इस तरह के समाचार सुनकर स्तब्ध है और भविष्य अंधकारमय प्रतीत हो रहा है, चाहे राजनीतिज्ञों का गिरता हुआ स्तर हो, चाहे डाक्टरों और न्यायालयों का गिरता हुआ स्तर हो, चाहे बाजारों में मिलावट का बोलबाला हो, चाहे शिक्षा का गिरता हुआ स्तर हो, चाहे आम आदमी के जीवन का गिरता हुआ स्तर हो।

ऐसा कोई देश का स्थान नहीं है जहाँ समाज का अवमूल्यन न हुआ हो, अब तक हम सभी काफी नीचे गिर चुके हैं अब इसको सुधारने का समय आ गया है। भारत वैसे भी भ्रष्टाचार में दिन प्रति दिन भ्रष्ट राष्ट्रों में अपनी अंतराष्ट्रीय ख्याति पाता जा रहा है।

अब समय आ गया है जब प्रबुद्ध वर्ग आत्मंथन करें। समाज का मार्गदर्शन करें और चरित्र उत्थान के लिये, समाज के मूल्यों को पुर्नस्थापित करने के लिए आगे आए। ये हमारी भारतीय संस्कृति के विपरीत है। हमारे पूर्वजों के दिए हुए संस्कारों के विपरीप है, ये समाज तो पश्चिम के मूल्यों के भविष्य की ओर इशारा करता है। जहाँ समाज का एक ही माप है वो है पैसा। क्या हम भी उसी समाज का अनुसरण करेंगे जो सीखने के लिये और आदर्शों की खोज में, शांति की खोज में भारत हमारे गुरुओं की शरण में आता है।

भटाव से हमें ऊपर उठना होगा सही रास्ता जो इस देश के महात्माओं ने स्वामी विवेकानंद ने, महात्मा गांधी ने, भगतसिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस और अनेकानेक साधु–संतों ने अपने जीवन को उन आदर्शों में जीकर, कष्ट सहकर भी सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं किया। महाराजा हरिशचंद्र को हम कैसे भूल सकते हैं। महान दानवीर कर्ण को कैसे भूल गए। आज पुनः एक बार भ्रष्टाचार समाप्ति और चारित्रिक उत्थान के लिए, समाज में शंखनाद करने का समय आ गया है। सभी राष्ट्रवादी संगठनों को एकजुट होकर समाज से इन बुराइयों को झाड़ू लगाकर बाहर फेंकना होगा।

स्वदेशी जागरण मंच विगत 20 वर्षों में सिर्फ स्वदेशी वस्तुओं और स्वदेशी अर्थव्यवस्था की बात नहीं करता। बल्कि विदेशी या चीनी सामान, मॉल संस्कृति का इत्यादि का विरोध इसलिए करता है क्योंकि ये सभी हमारी भारतीय संस्कृति और अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। हमारे लिए ग्राम को पूर्व इकाई बनाने की सोच है। हम मॉल संस्कृति को इसलिए विरोध करते हैं क्योंकि यह हमारे खुदरा व्यापार को समाप्त कर देगा।

हम स्वदेशी वस्तुओं से ज्यादा – स्वदेशी मानसिकता, स्वदेशी जीवनशैली, हमारी संस्कृति और हमारे सामाजिक मूल्य जिसमें हर भारतवासी का दर्द हम सभी का है। चरित्र के ऐसे उदाहरण हमारी संस्कृति के अलावा कहीं नहीं मिलेंगे। आजादी के लिए लाखों भारतवासियों ने हंसते–हंसते अपने प्राण न्योछावर कर दिए, अपना नाम अमर कर गए।

आज ऐसे उदाहरण कम ही देखने को मिलते हैं। एक बार पुनः स्वदेशी के सिद्धांतों पर चलकर देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का संकल्प लेने का समय आ गया है। एक बार फिर स्वदेशी का संदेश जन–जन तक पहुंचाए। आज टीवी चैनलों पर जो सैकड़ों की संख्या में हैं निरंतर 24 घंटे जिस तरह की मानसिकता के कार्यक्रम दिखाए जा रहे हैं वे ही सबसे ज्यादा हमारे मन पर प्रभाव डालते हैं। जिससे हम सभी को अपने–अपने घरों में एहतियात के साथ देखना चाहिए। पश्चिम की सभ्यता का भारत में अंधानुकरण ठीक नहीं है। ये सभी हमारे चरित्र और हमारी सोच को प्रभावित करते हैं। स्वदेशी जागरण मंच इन्हीं बातों को निरंतर प्रभावी रूप से पूरे देश में स्वदेशी मानसिकता स्थापित करने के अनथक प्रयास कर रहा है। ❑

(लेखक स्वदेशी जागरण मंच, जबलपुर के प्रांत कार्यालय प्रमुख हैं।)

लेख

भ्रष्टाचार हिंसा, सदाचार अहिंसा है

भारत में शांतिमय संघर्ष से क्रांति हुई है। शांति से आजादी मिली थी। इसलिए यहां के ज्ञान का विस्थापन, विकृति और विनाश अपेक्षाकृत कम है। अहिंसक क्रांति से आजादी मिलने का परिणाम हमारा लोकतंत्र आज भी सुरक्षित है। नदी कूच, जनसत्याग्रह और भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन या सत्याग्रह जहां जरूरत है, वहां चल पाते हैं। व्यवस्था में बदलाव भी करते हैं।

■ राजेन्द्र सिंह

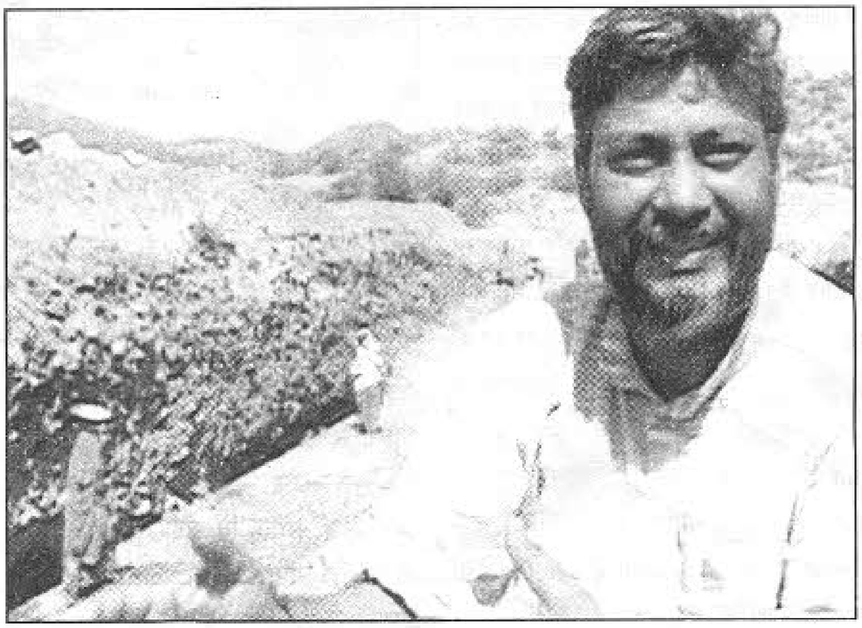

लूट से बचने या मानवीय और प्राकृतिक हालात को बेहतर बनाने का विचार ही क्रांति है। बदलाव लाने का विश्वास और अहसास लोक मानस में क्रांति शुरू है। यह क्रांति शांतिमय और रचनात्मक होती है, तो प्रकृतिमय जीवन की समृद्धि करता और अहिंसा को आगे बढ़ाती है।

हिंसक क्रांति होने के बाद विकास का रास्ता पकड़ती है। विकास की शुरूआत तो विस्थापन से ही होती है। फिर गैरबराबरी आती है। अंत में धरती का बुखार और मौसम का मिजाज बिगाड़ने वाला हिंसक विनाश होता है। यही जापान और रूस में हुआ था। अब चीन, अमेरिका और यूरोप में भी यही हो रहा है।

भारत में शांतिमय संघर्ष से क्रांति हुई है। शांति से आजादी मिली थी। इसलिए यहां के ज्ञान का विस्थापन, विकृति और विनाश अपेक्षाकृत कम है। अहिंसक क्रांति से आजादी मिलने का परिणाम हमारा लोकतंत्र आज भी सुरक्षित है। नदी कूच, जनसत्याग्रह और भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन या सत्याग्रह जहां जरूरत है, वहां चल पाते हैं। व्यवस्था में बदलाव भी करते हैं।

हमारी संवेदनशील सरकारें भी समय से निर्णय लेती हैं। जहां समय से जनदबाव को सम्मान देकर निर्णय नहीं लिया जाता है; वहीं भारत में भी हिंसक आंदोलन होते हैं। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में सरकार ने बहुत संवेदनशील होकर जल्दी निर्णय लिया तो हिंसा से हम सब बच गये। भ्रष्टाचार हिंसा ही है। भ्रष्टाचार से मुक्ति 'सदाचार' अहिंसा है। सदाचार केवल कानून से नहीं आता है। शिक्षण, रचना, संगठन सत्याग्रह से सदाचार बनता है।

भ्रष्टाचारी व्यवस्था में बदलाव ही अब छोटे समूह का 'साध्य' है। साध्य की सिद्धि हेतु सत्याग्रह और आन्दोलन साधन है। जैसे आजकल एक 'नदी कूच' नामक आन्दोलन चल रहा है। नदी और नालों को अलग–अलग रखने वाली व्यवस्था बनाने हेतु नदी नीति व नियम बनवाना इसका साध्य हैं। नदियों का नाला बनना भ्रष्टाचार है। नालों को नदी से अलग रखकर नाले को नदी बनाना सदाचार और अहिंसा है।

भ्रष्टाचारी व्यवस्था में बदलाव ही अब छोटे समूह का 'साध्य' है। साध्य की सिद्धि हेतु सत्याग्रह और आन्दोलन साधन है। जैसे आजकल एक 'नदी कूच' नामक आन्दोलन चल रहा है। नदी और नालों को अलग–अलग रखने वाली व्यवस्था बनाने हेतु नदी नीति व नियम बनवाना इसका साध्य हैं। नदियों का नाला बनना भ्रष्टाचार है। नालों को नदी से अलग रखकर नाले को नदी बनाना सदाचार

और अहिंसा है।

राज्य सरकारों पर जन दबाव बनाने हेतु नदी कूच का लोक शिक्षण चल रहा है। इसी शिक्षण प्रक्रिया में प्रत्येक राज्य की लोक नदी नीति तैयार करके मुख्यमंत्रियों को देना है। भारत की नदी नीति का प्रारूप श्री सलमान खुर्शीद जल संसाधन मंत्री को विश्व जल दिवस 22 मार्च, 2011 को दिल्ली में तथा श्री जयराम रमेश, पर्यावरण एवं वन मंत्री, भारत सरकार को 14 मार्च, 2011 के दिन इनके कार्यालय में पहुंचकर दे दी है।

यह गरीबों के जीवन और जीविका बचाने हेतु चल रहा नदी कूच अभी तक हिमाचल, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, उत्तराखण्ड और मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्रियों को नदी नीति प्रारूप प्रस्तुत कर चुका। अब इनसे इस नदी नीति को राज्य नदी नीति के रूप में घोषित कराना और इसके प्रकाश में कानून बनवाना है। यही नदियों के लिए आन्दोलन है।

आन्दोलन साध्य और साधन शुद्धि का ख्याल अपनी साधना में रखता है। जब भी साधन पाने के तरीकों की शुद्धि को आन्दोलन भूल जाता है, तो समाज साध्य से विचलित होकर जल्दी ही हटने भी लग जाता है। महात्मा गांधी ने आजादी आन्दोलन में साधन शुद्धि का बहुत ख्याल रखा था। इसीलिए उनके आन्दोलन की आत्मा में केवल सत्याग्रह ही दिखाई देता है। अभी साध्य और साधन शुद्धि के प्रति आन्दोलन सचेत दिखाई देते हैं। ये ही आन्दोलन सफल होंगे, जिनमें सत्य का आग्रह दिखाई देगा।

आजादी के आन्दोलन में साधना ही साध्य तक पहुंचाती थी, साधन की शुद्धि थी। इसीलिए साधना को सिद्धि मिली थी। यह प्रक्रिया लोकतंत्र में अब अपमानित हुई है। इसी कारण अब प्रायोजित आन्दोलन बहुत ऊपर दिखाई देते हैं। सहज स्वस्फूर्त सत्याग्रह या आन्दोलन नीचे दब जाते हैं।

भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल कानून बनवाने हेतु आन्दोलन चल रहा है। यह भ्रष्ट व्यवस्था को बदलने वाला है? इसे भारत के मीडिया ने अपना लिया है। मीडिया ने इसे बड़ा सम्मान दिया है। भ्रष्टाचार मुक्ति की साक्षरता कार्य इस आन्दोलन में मीडिया द्वारा किया जाता तो अच्छा रहता है।

समाज स्वयं भी प्राकृतिक संसाधनों का समता–सादगी से उपयोग करें। तभी लूटने वालों से लड़ सकते हैं। ऐसी लड़ाई ही सफलता तक पहुंच सकती है। समता–सादगी से प्राकृतिक संसाधनों का लोक उपयोग करेगा तभी भ्रष्टाचार मिटेगा। सदाचार पनपेगा।

सदाचार नीचे से ऊपर जाता है। भ्रष्टाचार ऊपर से ही नीचे आता है। नीति–नियम का बनना और पालना कराना ऊपर के चालू भ्रष्टाचार के कारण घातक होता है। यह पूरी प्रक्रिया अतिक्रमण और भ्रष्टाचार की तरफ ही मुड़ जाती है। ऊपर से ऊपर ज्यादातर भ्रष्टाचारी शक्तियां

आन्दोलन साध्य और साधन शुद्धि का ख्याल अपनी साधना में रखता है। जब भी साधन पाने के तरीकों की शुद्धि को आन्दोलन भूल जाता है, तो समाज साध्य से विचलित होकर जल्दी ही हटने भी लग जाता है। महात्मा गांधी ने आजादी आन्दोलन में साधन शुद्धि का बहुत ख्याल रखा था। इसीलिए उनके आन्दोलन की आत्मा में केवल सत्याग्रह ही दिखाई देता है। अभी साध्य और साधन शुद्धि के प्रति आन्दोलन सचेत दिखाई देते हैं। ये ही आन्दोलन सफल होंगे, जिनमें सत्य का आग्रह दिखाई देगा।

अपने हित में बड़े लोक निर्णय को भी बदलवाती हैं। धन, शक्ति, जनहित को दर किनार करके कुछ ही लोगों के हित में कानून–कायदे बना देती है।

महात्मा गांधी यूरोप की संसद को इसीलिए वैश्या कहते थे। फिर भी वे भारत में संसद बनाने को ही उचित मानते थे। लोक समझ, लोक शक्ति और लोक व्यवहार, लोक संस्कार को लोक समृद्धि में लगाने का एक मात्र तरीका संसद को ही मानते थे। संसदीय व्यवस्था जब भी ठेकेदारी से चलती है, तभी महात्मा गांधी संसद को वैश्या कहते थे। लोक समझदारी से गठित संसद को वे बहुत सम्मान करते थे। इसीलिए भारत की लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था भी थी।

संसद को ठेकेदारी से दूर रखने वाला काम लोकपाल कानून बनाना, जनसत्याग्रह, नदी कूच यमुना सत्याग्रह तथा आन्दोलनों का राष्ट्रीय समन्वय जगह–जगह शिक्षण, रचना, संगठन व संघर्ष में जुटकर कर रहे हैं। आजकल भारत में नए आन्दोलन उभर रहे हैं। महात्मा गांधी के सत्याग्रह की रूपरेखा नहीं बन रही है। भारत की संसदीय व्यवस्था को सुधारने वाला सत्याग्रह अब बहुत जरूरी है। हमारी संसदीय सदाचारी लोक चेतना जरूरी है। ये कार्य अब नीर–नारी–नदी को सम्मान देने वाली समता–सादगी पूर्ण व्यवस्था के साध्य वाले सत्याग्रह से ही होगी।

संसद को ठेकेदारी से दूर रखने वाला काम लोकपाल कानून बनाना, जनसत्याग्रह, नदी कूच यमुना सत्याग्रह तथा आन्दोलनों का राष्ट्रीय समन्वय जगह–जगह शिक्षण, रचना, संगठन व संघर्ष में जुटकर कर रहे हैं। आजकल भारत में नए आन्दोलन उभर रहे हैं। महात्मा गांधी के सत्याग्रह की रूपरेखा नहीं बन रही है। भारत की संसदीय व्यवस्था को सुधारने वाला सत्याग्रह अब बहुत जरूरी है। हमारी संसदीय सदाचारी लोक चेतना जरूरी है। ये कार्य अब नीर–नारी–नदी को सम्मान देने वाली समता–सादगी पूर्ण व्यवस्था के साध्य वाले सत्याग्रह से ही होगी।

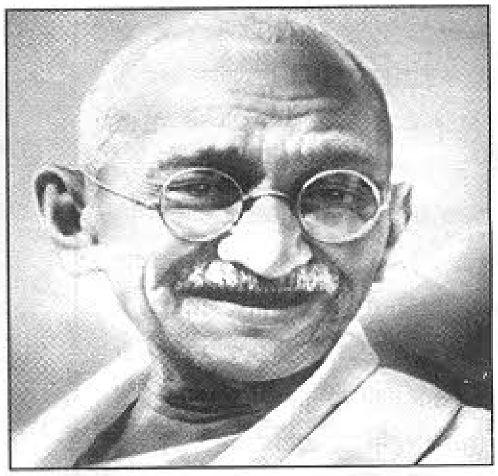

लोकतंत्र समृद्धि हेतु सत्याग्रह जरूरी है। संसद की समृद्धि लोकाधार से बनती है। लोक शिक्षण संसद या लोकतंत्र का जरूरी काम होता है। एक छोटा समूह पूरे राष्ट्र के लोक का शोषण करने लगे। भ्रष्टाचार से लोक पीड़ित हो जाये तब एक समूह भ्रष्टाचार की पीड़ा से मुक्ति हेतु आगे आना और हल खोजना आवश्यक नहीं है। संसदीय व्यवस्था लोक हितकारी और जिम्मेदार बने इस हेतु सभी स्तर पर प्रयास जरूरी है।

जब कोई व्यक्ति या समूह सत्य के लिए आग्रही है, तो ही उसे 'सत्याग्रही' कहते हैं। लोक जब अपना जीवनाधार लूटता देखकर लड़ने लगता है तो उसे 'आन्दोलन' कहते हैं। अन्याय का प्रतिकार करने तथा रचना करने वाली प्रक्रिया को परिवर्तन कहते है। बदलाव के लक्ष्य को जिस तरीके से हम प्राप्त करते हैं वही आन्दोलन या सत्याग्रह कहलाता है।

आन्दोलन के प्रभाव स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। भारत के लोकतंत्र को बचाने और मजबूत करने में इनकी खास भूमिका है। आन्दोलन भारत में सफलता पाते ही हैं। यही हमारे लोकतंत्र की खासियत है। शुद्ध साध्य को पूर्ण करने वाली साधना से ही सत्याग्रह चले, तभी इनका प्रभाव स्थाई होगा।

बे जमीन और बे घरों को जमीन मिले इस हेतु 'जन सत्याग्रह 2012' एकता परिषद द्वारा देशभर में चालू है। ये गरीब–बेसहारा को संगठित करके जमीनी हकदारी दिलाने का कार्य छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश के साथ पूरे देश में चला रहे है। इसी प्रकार विकास द्वारा विस्थापन, विकृति और विनाश विरोधी आन्दोलनों को राष्ट्रीय समन्वय द्वारा चलाया जा रहा है। ये सभी आन्दोलन आत्मा से एक है। इनके साध्य भी एक ही दिखाई देते है।

साधन भिन्नता है। सत्याग्रह तो साध्य–साधन और शुद्धि का ख्याल रखने वाला होता है। आन्दोलन कभी–कभी लालच को पूरा करने और लाभ कमाने हेतु भी होता है। अहिंसक आन्दोलन सदाचारी तथा हिंसक साध्यचारी होता है। ❑

भ्रष्टाचार के बाद देश

यदि भ्रष्टाचार समाप्त हो जाता है तो उसके बाद देश में क्या क्या हो सकता है और क्या क्या नहीं। इसके लिए भी सोच कर देशवासियों को तैयार रहने की आवश्यकता है। देश की ज्वलंत समस्याओं में से भ्रष्टाचार प्रमुख है। इसी समस्या के कारण देश के 64 वर्ष के स्वतंत्रता के जीवन में गरीब और गरीब व अमीर और अमीर हो गया है तथा भारत के काले धन से विदेशी बैंक व उनके देश फलफूल रहे हैं जबकि भारत एक गरीब देश बन कर रह गया है।

■ डॉ. सूर्य प्रकाश अग्रवाल

भ्रष्टाचार समाप्त हो गया तो उसके बाद देश में क्या होगा? इसका उत्तर आश्चर्यजनक हो सकता है। कुछ संजीदा हो सकते है और कुछ उत्तर गैरसंजीदा भी हो सकते है। परन्तु इतना तो एक दम से सही है कि भ्रष्टाचार के उन्मूलन के उपरांत भारत देश पुनः सोने की चिडिया बन जायेगा। परन्तु इसके लिए नागरिकों को जो मुसीबतें उठानी पड सकती है वह भी कुछ कम नहीं होगी।

अन्ना हजारे व बाबा रामदेव के द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो अलख जगाया गया है वह अब पूरे देष में ही तेजी से फैलता जा रहा है और एक जन आंदोलन का रूप लेता जा रहा है यदि संभवतः इन आंदोलनों से यदि भ्रष्टाचार समाप्त हो जाता है तो उसके बाद देष में क्या क्या हो सकता है और क्या क्या नहीं। इसके लिए भी सोच कर देषवासियों को तैयार रहने की आवष्यकता है। देष की ज्वलंत समस्याओं में से भ्रष्टाचार प्रमुख है। इसी समस्या के कारण देष के 64 वर्ष के स्वतंत्रता के जीवन में गरीब और गरीब व अमीर और अमीर हो गया है तथा भारत के काले धन से विदेषी बैंक व उनके देष फलफूल रहे हैं जबकि भारत एक गरीब देष बन कर रह गया है।

भ्रष्टाचार समाप्त हो गया तो उसके बाद देष में क्या होगा? इसका उत्तर आश्चर्यजनक हो सकता है। कुछ संजीदा हो सकते है और कुछ उत्तर गैरसंजीदा भी हो सकते है। परन्तु इतना तो एक दम से सही है कि भ्रष्टाचार के उन्मूलन के उपरांत भारत देष पुनः सोने की चिडिया बन जायेगा। परन्तु इसके लिए नागरिकों को जो मुसीबतें उठानी पड सकती है वह भी कुछ कम नही होगी। भारतवासी अब तक भ्रष्टाचार के वातावरण में रहने के आदि हो चुके है। इतने बड़े-बड़े घोटाले देष में प्रकाष में आये परन्तु देष के किसी कोने से उनके विरोध में कोई आवाज नही आयी। भ्रष्टाचार के बाद देष में दूध की नदियां बहेंगी क्योंकि थानेदार दुधारु पशुओं से लदे ट्रकों को रोक लेगा और पशु चिकित्सक भी उनको काटने के लिए प्रमाण पत्र नहीं दे सकेगा। हमारी तमाम षिक्षा, तमाम आदर्षों का मजाक उस समय बन जाता है जब भ्रष्टाचार होता है। भारत का युवक आईएएस जैसी उच्च श्रेणी की परीक्षा कठिन परिश्रम करके उत्तीर्ण करके अधिकारी बनता है परन्तु वह अपने संस्कार, आदर्ष, कर्तव्यनिष्ठा जैसे गुणों को ताक पर उठा कर रख देता है तथा भ्रष्टाचार से करोड़ों रुपयों के धन का स्वामी कुछ ही समयोपरान्त बन जाता है। यह भी किसी तौहीन से कम नहीं है।

युवक षिक्षित होकर भी भ्रष्ट हो गया और इस कदर भ्रष्ट हो गया कि उसकी भ्रष्टता के विरुद्ध कोई अन्य आदमी आंदोलन कर रहा है। युवक रात दिन किताबों में माथापच्ची करके उच्च पद प्राप्त करता है और अपनी षिक्षा व संस्कार पदग्रहण करने के बाद भूल जाता है। आज युवक स्कूलों व महाविद्यालयों व विष्वविद्यालयों में केवल उपाधि (डिग्री) ही प्राप्त कर रहे है। उनमें संस्कार, राष्ट्रभक्ति व निष्ठा, आदर्ष, कर्तव्यबोध व कर्तव्यनिष्ठा जैसे गुण उत्पन्न ही नहीं हुए है। भ्रष्टाचार में लिप्त होकर उनके जीवन की एक कलंकित कहानी सीबीआई द्वारा पकडे जाने पर समाज के सामने आती है।

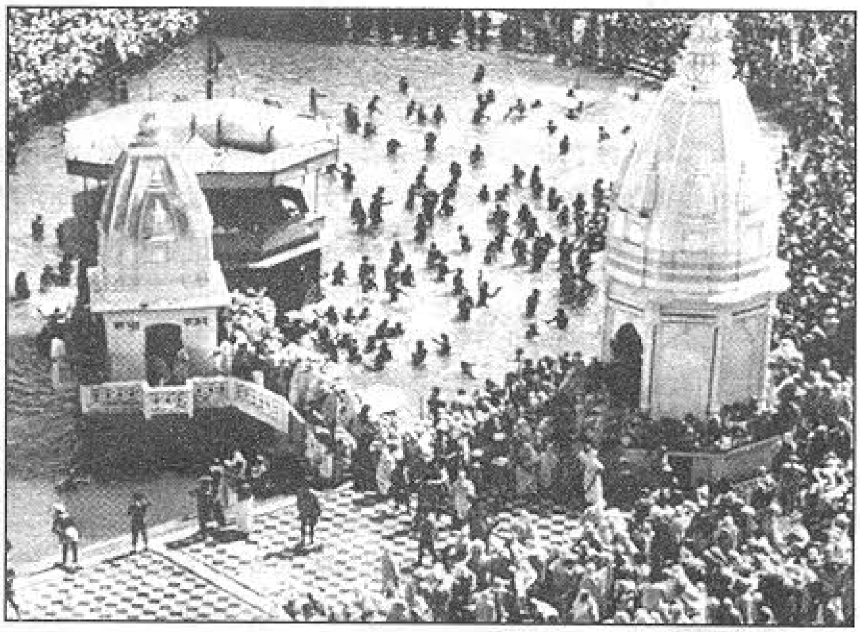

शहर के नागरिकों को सडक पर चलने के लिए जब एक सिपाही के डंडे की जरुरत पडती है तो इससे ज्यादा नागरिकों का क्या अपमान होगा? क्योंकि शहर में रहने वाले व गर्व से स्वयं को ग्रामीण के स्थान पर शहरी संबोधित करने के उपरान्त भी हमको सड़क पर अनुषासित रूप से ढंग से चलने के लिए एक दसवीं कक्षा पास सिपाही की आवष्यकता पड़ती है। भारत में भ्रष्टाचार इस कदर बढ़ चुका है कि एक 73 वर्ष के बूढ़े फौजी व्यक्ति अन्ना हजारे व योगी रामदेव को आंदोलन चला कर भ्रष्टाचार के उन्मूलन करने का प्रयास करना पड रहा है और फिर इन महानुभावों को भ्रष्ट राजनेता, अफसर, बुद्धिजीवी तरह तरह के बहाने, जांच, भय इत्यादि दिखा कर इस कदर भयभीत करने की कोषिष करते है कि उन्होंने जैसे कोई गलत बात व मुददे को लागू करने के लिए आंदोलन छेड़ रखा हो। विष्व में भ्रष्टाचारी देषों की सूची में हम (भारत) प्रथम पांच में रहते है। क्या इससे हम गौरवांतिक महसूस करते है? भ्रष्टाचार के उन्मूलन के बाद देष में निम्न में से कुछ हो सकता हैं।

(1) लोगों के भवनों के उल्टे सीधे नक्षे पास नहीं होगें और सही तरीके से भवन निर्माण करने में लोगों को भारी परेषानी का सामना करना पड सकता है।

(2) बिजली की चोरी नहीं कर सकेगें। हीटर का प्रयोग खाना बनाने व कमरा गर्म करने के लिए नहीं कर सकेगें, रसोई गैस की मांग बढ़ जायेगी, फालतू में समर्बेषेबिल पम्प से पानी चला कर पानी का दुरुपयोग नहीं कर पायेंगे।

(3) टीवी के विभिन्न चैनलों पर सनसनी खेज स्टिंग आपरेषन वाली चटपटी खबरें उपलब्ध नहीं हो पायेंगी और बेरुखी खबरों को कौन देखेगा जिससे टीआरपी कम होने से चैनलों को विज्ञापन नहीं मिल सकेगें।

(4) बिना टिकट रेल व बस में यात्रा नहीं कर सकेंगे, पिछले दरवाजे से दलाल के सहयोग से रेल सीट का आरक्षण नहीं करवा सकेंगे। रास्ते में टीटीई से सीट भी रुपया देकर नहीं प्राप्त कर सकेगें, सीट उसको मिल जायेगी तो पहले आयेगा और पैसे वाले देखते रह जायेगें। टीटीई के ईमानदारी से भ्रष्टाचार से कमाये हुए धन से पैसे वाले हुए लोग आराम से सफर नहीं कर सकेगें।

(5) सरकार के द्वारा कल्याणकारी योजनाऐं नहीं बन सकेंगी। बाढ, भूकम्प,

वह दिन शुभ होगा जिस दिन लोग भारतीय संस्कार में रह कर पल सकेंगे व बढ़ सकेंगे और भ्रष्टाचार को सदा–सदा के लिए नमस्कार कर सकेंगे। वास्तव में देश में दूध व दही की नदियां बह सकेंगी और देश में कोई नागरिक अभावग्रस्त नहीं रह सकेगा फिर यह कोई नहीं पूछ सकेगा कि भ्रष्टाचार समाप्त हो गया तो क्या होगा? जब प्रश्न ही अस्तित्व में नहीं होगा तो उत्तर भी नहीं होगा।

महामारी, सूखा राहत कार्य में रुपया गरीबों को सीधा पहुंचेगा तो अफसर दिन भर धूप ताप में घर घर रुपया बांटते फिरेंगे और अफसरों के बच्चे विदेषों में पढ नहीं पायेगें।

(6) कल्याणकारी योजनाओं का लाभ 100 में से 10 गरीब लोगों को अवष्य मिल सकेगा।

(7) निर्माण कार्य रुक जायेगा तथा उससे देष के विकास का पहिया रुक जायेगा क्योकि भ्रष्टाचार में कमाये धन को ही भवन निर्माण में लगा कर मकान में भव्यता लाने की कोषिष की जाती है तथा मकान को दिखा कर दूसरे पर रौब गालिब किया जाता है।

(8) जब मकान नहीं बनेगें तो उससे जूडे लक्जरी सामग्री बनाने वाले उद्योगों का विकास रुक जायेगा और ऐसे उद्योग बंदी के कगार पर पहुंच जायेंगे।

(9) सरकारी अस्पताल में भीड़ लग जायेगी क्योकि वहां चिकित्सा उपलब्ध होगी, मरीज को दवाई मिलेगी, आपरेषन होगें, एक्सरें निकाल सकेंगे, टूटे पैर पर मुफ्त प्लास्टर चढ सकेंगा, आंखों के ऑपरेषन हो सकेगे, कैंसर का ईलाज हो सकेगा। निजी नर्सिंग होमों में ताला लग जायेगा। पुलिस वालो से मनचाहा केस नहीं बनवाया जा सकेगा।

(10) बिना दहेज के विवाह हो सकेगे क्योंकि भ्रष्टाचार से ही कमाया गया धन दहेज में दिया जाता है। कन्याओं की घटती जनसंख्या बढ़ सकेगी। लड़का व लड़की में सामाजिक अंतर कम हो जायेगा।

(11) कम पढे लिखे व नाकारा लोगों को रिष्वत के आधार पर नौकरी नहीं मिल सकेगी जिससे खेतों में काम करने के लिए युवा मजदूर उपलब्ध हो सकेंगे। षिक्षा के आधार पर ही नौकरी मिलेगी तो युवक षिक्षा ग्रहण करने के लिए मेहनत ज्यादा करेगें।

(12) गोदामों में अनाज सड़ेगा नहीं भूखों को भरपेट भोजन मिल सकेगा। किसान के खेत को पानी, खाद, बीज व बिजली समय पर मिल सकेगी। किसान का क्रेडिट कार्ड आसानी से बन सकेगा व उसके खेत की नाप ठीक हो सकेगी जिससे न्यायलायों में मुकदमे कम हो सकेगें।

(13) सेनाओं के पास कमीषन में खरीदे गई खराब किस्म की तोपें, बम, रिवाल्वर, कारतूस, पनडुब्बी इत्यादि नहीं होगी उन्हें विष्व में सबसे बढ़िया युद्ध सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी जिससे सैनिकों का हौसला बुलन्द हो सकेगा और शत्रु में भय व्याप्त होगा।

(14) संसद व विधान सभा में मतदाताओं पर करोड़ों रुपया व्यय करके अपराधी व राजनीति को धंधा बनाने वाले लोग सांसद व विधायक नहीं बन सकेगें। केवल वे ही लोग संसद व विधानसभा में पंहुच पायेगें जो कि देष व प्रदेष के लोगों की सेवा निष्ठापूर्वक करना चाहते है। गली–गली में लम्बे–लम्बे सफेद कुर्ते, पायजामे व सफेद जूते पहन कर घूम रहे राजनेता गायब हो जायेगे उनकी वोट बैंक की राजनीति समाप्त हो जायेगी। ऐसे गली छाप राजनेता थाने में जाकर गुनहगार को नहीं छुडा सकेगें।

वह दिन शुभ होगा जिस दिन लोग भारतीय संस्कार में रह कर पल सकेगे व बढ़ सकेगें और भ्रष्टाचार को सदा–सदा के लिए नमस्कार कर सकेगें। वास्तव में देष में दूध व दही की नदियां बह सकेगी और देष में कोई नागरिक अभावग्रस्त नहीं रह सकेगा फिर यह कोई नहीं पूछ सकेगा कि भ्रष्टाचार समाप्त हो गया तो क्या होगा? जब प्रष्न ही अस्तित्व में नहीं होगा तो उत्तर भी नहीं होगा। ❑

:: स्वदेशी गीत ::

संघर्ष पर्व के लिये, नवीन प्राण चाहिये,
नवीन प्राण चाहिये।।धृ।।
गुलाम देश हो गया, तमस–मय दिशा मही
स्वदेशी चाह ढल चुकी विदेशी सोच हो गयी,
गुलाम मनोवृत्ति को, स्वदेशी ज्ञान चाहिये,
स्वदेशी ज्ञान चाहिये।।1।।
ढल रहा ईमान है कि, विदेशी तंत्र छा गया,
दिशा–दिशा पुकारती, स्वदेशी मंत्र हो नया,
विदेशी माल बिक रहा, स्वदेशी की मांग चाहिये,
स्वदेशी की मांग चाहिये।।2।।
युवक कमर कसो कि, चारों ओर भ्रष्टाचार है,
इसे मिटाने के लिये, जन मानस तैयार है,
पगों में आंधियाँ भरे, स्वदेशी गान चाहिये,
स्वदेशी गान चाहिये।।3।।

– लेखक रमेश तांबे

दृष्टिकोण

जैतापुर : आणविक ऊर्जा के विरोध में उठती आवाज

जापान में आई भीषण सुनामी की त्रासदी के फलस्वरूप फुकुशीमा परमाणु ऊर्जा संयंत्र से रेडियोधर्मी विकरण के मद्देनजर दुनिया भर में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की सुरक्षा के बारे में पुनः सवाल उठने शुरू हो गये हैं। सुनामी के कारण फुकुशीमा परमाणु संयंत्र की शीतलन प्रणाली (कूलिंग सिस्टम) पूरी तरह से तहस नहस हो गया। ऐसे में रिऐक्टर में भारी गर्मी हो जाने से उसमें विस्फोट होने लगे, जिससे ईंधन छड़ों को नुकसान हुआ और आसपास के वातावरण में रेडियोधर्मी पदार्थ फैलने लगे. . .

■ डॉ. अश्विनी महाजन

भारत सरकार ने जैतापुर आणविक विद्युत परियोजना के तमाम विरोधों को दरकिनार करते हुये, परियोजना को हरी झंडी दे दी है। यह आणविक ऊर्जा के पक्ष में सरकार की हठधर्मिता का एक उदाहरण कहा जा सकता है। कुछ वर्ष पूर्व तक भारत सरकार को यह मलाल था कि आणविक ऊर्जा की दृष्टि से भारत में कुछ अधूरापन है। कारण यह था कि भारत यूरेनियम आपूर्ति की दृष्टि से आत्मनिर्भर नहीं था। यही नहीं आणविक ऊर्जा के संदर्भ में जिन देशों के पास प्रौद्योगिकी थी, उसे उन देशों ने भारत को उपलब्ध कराने पर प्रतिबंध लगाया हुआ था। ऐसे में बहुचर्चित भारत–अमेरिकी आणविक समझौता किया गया। उस समझौते के अंतर्गत अमेरिका ने कुछ शर्तों के तहत भारत पर आणविक प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने हेतु प्रतिबंध समाप्त कर दिया। उसके लिये जरूरी था कि देश की संसद इस समझौते को मान्यता देते हुये विधेयक पारित करे।

ऐसे में देश के प्रमुख राजनीतिक दलों ने आपत्ति दर्ज कराई। भारतीय जनता पार्टी, वामपंथी दलों सहित कई राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया। ऐसे में पैसे का खेल भी हुआ और अंतोगत्वा भारत अमरीकी समझौते पर संसद की मोहर लग गई। अन्य बातों के साथ–साथ संसद द्वारा पारित कानून में 'लिमिटेड लायबिल्टी' यानि सीमित देयता प्रावधान को शामिल किया गया। इस प्रावधान का मतलब यह था कि दुर्घटना होने की सूरत में आणविक ऊर्जा कंपनी की देयता सीमित रहेगी। बड़ी से बड़ी दुर्घटना होने पर भी आणविक कंपनी की दयता मात्र 1500 करोड़ रूपये तक सीमित रहेगी। भारत–अमरीकी आणविक

समझौते और सीमित देयता प्रावधान (जो अमरीकी सरकार के दबाव में शामिल किया गया) के कारण इसका भारी विरोध देश में हुआ और एक वक्त तो ऐसा आया कि सरकार का समर्थन करने वाले वामपंथी राजनीतिक दलों ने सरकार से समर्थन वापिस ले लिया। सरकार को अपना बहुमत जुटाने में काफी मशकक्त करनी पड़ी। यदि विकिलिक्स खुलासों की बात मानें तो भारी मात्रा में पैसे के लेन–देन से सांसदो के वोट खरीद कर येन–केन–प्रकारेण सरकार को बचाया जा सका।

जापान की त्रास्दी

सरकार ने आणविक ऊर्जा को विकास के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया और सत्ता में प्रमुख दल कांग्रेस ने इस आधार पर चनाव लडा। कांग्रेस को पहले से बेहतर समर्थन भी मिला और इस बार बिना वामपंथी राजनीतिक दलों के सहयोग के कांग्रेस ने कुछ अन्य दलों से सहयोग लेते हुए सरकार का गठन कर लिया। जापान में आई भीषण सुनामी की त्रास्दी के फलस्वरूप फुकुशीमा परमाणु ऊर्जा संयंत्र से रोडियोधर्मी विकरण के मद्देनजर दुनिया भर में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की सुरक्षा के बारे में पुनः सवाल उठने शुरू हो गये हैं। सुनामी के कारण फुकुशीमा परमाणु संयंत्र की शीतलन प्रणाली (कूलिंग

सिस्टम) पूरी तरह से तहस नहस हो गया। ऐसे में रिऐक्टर में भारी गर्मी हो जाने से उसमें विस्फोट होने लगे, जिससे ईंधन छड़ों को नुकसान हुआ और आसपास के वातावरण में रेडियोधर्मी पदार्थ फैलने लगे। फुकुशीमा संयंत्र के आसपास के 20 किलोमीटर क्षेत्र के निवासियों को वहां से बाहर निकाल लिया गया और लोगों को चेतावनी दी गई है कि इस क्षेत्र में उत्पादित दुध एवं अन्य खाद्य पदार्थों का सेवन न करें। फुकुशीमा के आसपास का समुद्री पानी एवं समुद्री जीवन रेडियोधर्मिता से बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। दुर्घटना के एक महीने के बाद भी रेडियोधर्मिता के फैलने पर काबू नहीं पाया जा सका है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जापानी लोगों के अद्‌भुत अनुशासन के बावजूद ऐसा हो रहा है।

सुरक्षा उपायों पर सवालिया निशान

इस दुर्घटना से उत्पन स्थिति के मद्देनजर आणविक रिऐक्टरों के सुरक्षा मानकों एवं आपदा प्रबंधन की संभावनाओं पर एक सवालिया निशान लग गया है। ऐसे में स्वभाविक ही है कि जहां–जहां आणविक रिऐक्टर लगाये जाने की परियोजनाएं लग रही हैं या लगने वाली हैं, वहां के निवासी उसका विरोध करेंगे। सरकार का यह पुरजोर प्रयास रहेगा कि वे किसी न किसी प्रकार से लोगों को समझा–बुझाकर या किसी अन्य प्रकार से कोशिश करते हुए, इस प्रकार के आन्दोलन को कुन्द कर दें। ऐसा होता है या नहीं, यह तो समय ही बताएगा, लेकिन यह बात पक्की है कि अब किसी भी क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा के लिए रिऐक्टर लगाना सरकार के लिए टेढ़ी खीर होगी। वर्तमान में भारत में 19 आणविक रिऐक्टर काम कर रहे हैं, जिनकी कुल क्षमता 4000 मेगावाट है। भारत–अमरीकी समझौते से प्रफुल्लित सरकार की योजना है कि वर्ष 2030 तक इस क्षमता को बढ़ाकर 60,000 मेगावाट कर दिया जाऐगा। दिसम्बर 2009 में दुनिया में कुल 436 परमाणु रिऐक्टर थे। अमेरिका, जापान और फ्रांस तीनों मिलकर दुनिया का 56.5 प्रतिशत आणविक ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, दुनिया की ऊर्जा आवश्यकताओं का मात्र 6.5 प्रतिशत आणविक ऊर्जा से प्राप्त होता है।

विकसित देशों का मोह भंग

ध्यातव्य है कि अमेरिका जो अपनी आवश्यकता का 19 प्रतिशत परमाणु ऊर्जा से प्राप्त करता है, अब और अधिक आणविक ऊर्जा संयंत्र नहीं लगा रहा है। जापान में भी आणविक ऊर्जा अब पहले से कम उत्पादित हो रही है, इसका प्रमुख कारण यह है कि 2007 में आये भारी भूकम्प के चलते अब जापान का काशीवजाकीकरिवा न्यूकिलियर रिऐक्टर बंद पड़ा है। पिछले वर्ष दुनिया का आणविक ऊर्जा का उत्पादन 1.8 प्रतिशत घट गया। जापान के कुछ रिऐक्टर रिटायर हो गये और नये रिऐक्टर नहीं लगे। ऐसा कहा जा रहा है कि आणविक ऊर्जा का भविष्य अब विकासशील देशों में है। भारत में राजस्थान में पिछले वर्ष 6 रिऐक्टर लगाये गये। भारत सरकार की योजना है कि अब जैतापुर महाराष्ट्र के साथ–साथ पश्चिमी बंगाल, गुजराज, आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु प्रत्येक राज्य में 10,000 मेगावाट वाले 5 आणविक ऊर्जा पार्क स्थापित किये जायेंगे।

भारत–अमरीकी आणविक समझौते का प्रारंभिक विरोध इस कारण से किया गया था कि इस समझौते के कारण देश में विदेशों पर निर्भरता बढ़ जायेगी, क्योंकि आणविक ऊर्जा संयंत्र विदेशी प्रौद्योगिकी, विदेशी संयंत्रों एवं विदेशी ईंधन पर आधारित होंगे, लेकिन जापान की फुकुशीमा परमाणु संयंत्र की दुर्घटना के बाद अब परमाणु रिऐक्टरों के विरोध को एक नया आयाम मिला है। बिजली आज की आवश्यकता है और बिजली के बिना विकास बाधित होता है, यह सही है। लेकिन प्रश्न यह है कि यह विकास किसके लिए है? जापान में नागासाकी–हिरोशीमा पर अमेरिका द्वारा गिराये गये परमाणु बमों की त्रास्दी से विष्व अभी तक उबर नहीं पाया है। भूकम्प और सुनामी की आशंकाएं लगातार बनी रहती हैं। उधर दुनिया भर में आतंकवाद सिर उठा रहा है। परमाणु संयंत्र आतंकवादियों के लिए आसान टारगेट होते हैं। ऐसे में रेडियोधर्मिता के विकरण से यदि मानवता ही समाप्त हो जायेगी तो इस विद्युत का और इस विकास का कोई मतलब नहीं रहेगा।

आने वाली पीढ़ियों पर भार

एक अन्य पक्ष जिसकी तरफ अभी तक बहुत कम ध्यान जाता है, वह यह है कि वर्तमान प्रौद्योगिकी के आधार पर लगाए जा रहे परमाणु संयंत्र का एक निष्चित जीवन काल होता है। उसके बाद वे संयंत्र रिटायर कर दिये जाते हैं। इन रिटायर किए गए संयंत्रों की देखभाल और शीतलन एक अनिवार्य प्रक्रिया है। किसी भी परमाणु संयंत्र का जीवन 30 से 40 वर्ष से ज्यादा नहीं होता और उसके बाद हजारों वर्षों तक आने वाली पीढ़ियों को उसके शीतलन और प्रबंधन की जिम्मेवारी संभालनी होगी। चूक होने की स्थिति में भयानक दुर्घटनाएं हो सकती है। 30–40 वर्षों तक वर्तमान पीढ़ी के लिए बिजली का प्रबंध करते हुए आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बोझ छोड़कर जाना किसी भी पीढ़ी के लिए उचित नहीं है। बिजली चाहे जितनी भी जरूरी हो हमें विकरण और प्रदूषण रहित अक्षय ऊर्जा का विकास ही एक मात्र उपाय है। ❑